

होमगार्ड भर्ती के लिए आई युवती से एंबुलेंस में गैंगरेप

गया। बिहार के गया में होमगार्ड भर्ती के लिए आई लड़की (26) के साथ एंबुलेंस में गैंगरेप हुआ है। ड्राइवर और टेक्नीशियन ने वारदात को अंजाम दिया है। दोनों ने गैंगरेप के बाद चुप रहने की धमकी देते हुए पीड़ित को अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात 24 जुलाई (गुरुवार) की है। इसका खुलासा शुक्रवार देर रात हुआ है। लड़की बीएमपी-3 के मैदान में होमगार्ड भर्ती के लिए पहुंची थी। दौड़ते समय बेहोश होकर गिर गई। मौके पर मौजूद एंबुलेंस से उसे अस्पताल भेजा गया। एंबुलेंस में एक भी महिला स्टाफ को नहीं भेजा। रास्ते में ड्राइवर और टेक्नीशियन की नीयत बिगड़ गई। पहले चलती एंबुलेंस में टेक्नीशियन ने रेप किया, फिर गाड़ी सुनसान जगह पर रोककर ड्राइवर ने दरिंदगी की। पीड़ित ने अस्पताल पहुंचकर महिला डॉक्टर को पूरी कहानी बताई। जिसके बाद पुलिस ने एक्शन में लिया।

जयपुर में सीएम ऑफिस-एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी

जयपुर। मुख्यमंत्री के ऑफिस और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। फौरन सीएम ऑफिस के साथ ही एयरपोर्ट पर चेकिंग शुरू की गई, हालांकि एक घंटे की छानबीन के बाद पुलिस को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। शनिवार को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑफिशियल इमेल आईडी पर मेल कर लिखा गया- एक से दो घंटे बाद सीएम ऑफिस और एयरपोर्ट को उड़ा दिया जाएगा। एयरपोर्ट पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, बम स्कॉड और सिविल डिफेंस की टीमों ने छानबीन की। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी एंटी बम स्कॉड और पुलिस की टीम पहुंची। यहां भी कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।

राज्यपाल ने अपराजिता विधेयक ममता सरकार को वापस भेजा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस ने ममता बनर्जी सरकार द्वारा लाए गए अपराजिता बिल को राज्य सरकार को लौटा दिया है। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इस बिल पर गंभीर आपत्ति जताई है। केंद्र का कहना है कि यह बिल भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में बदलाव करता है और इसमें दुष्कर्म जैसे अपराधों में बहुत सख्त सजा का प्रावधान है। इस बिल को 6 सितंबर 2024 को राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेजा था, हालांकि तभी गवर्नर बोस ने बिल में कई खामियों की बात कही थी। दरअसल, 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर के बाद राज्य सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे। ममता सरकार ने 3 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी-रेप बिल पेश किया था।

सीएम योगी का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को क्पुलिस में 20 प्रतिशत आरक्षण

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को 26वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि कारगिल युद्ध पाकिस्तान द्वारा थोपा गया था, जिसका भारत ने ऑपरेशन विजय के तहत दुश्मन को करारा जवाब



दिया। उन्होंने कहा कि कारगिल एक चुनौतीपूर्ण जगह थी जहाँ दिन में भी तापमान माइनस 50 डिग्री रहता है। लेकिन पाकिस्तान के कायर भारतीय सेना के

गुलाम नबी आजाद ने दिया राजनीतिक एकजुटता मंत्र, तभी मिलेगी जम्मू-कश्मीर को अपनी पहचान

नई दिल्ली। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (डीपीएपी) के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एकीकृत राजनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया है। आजाद ने जम्मू-कश्मीर में विकास की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जहां केंद्र सरकार की परियोजनाएं आगे

बढ़ रही हैं, वहीं राज्य स्तर की परियोजनाएं पूरी तरह ठप पड़ी हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों ने संसद में इसका (राज्य का दर्जा) वादा किया है। कुछ गलतियां होती गई जिससे देरी हुई। पहले, सरकार के समक्ष मांग रखी जानी चाहिए लेकिन लोग तुरंत सड़कों पर उतर आते हैं। आजाद ने कहा कि इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए।

दोस्त वॉट्सएप ग्रुप पर बोला- मराठी में बात करो, साथियों ने अगले दिन हॉकी स्टिक से पीटा

मुंबई। नवी मुंबई में एक छात्र के मराठी में बात करने के लिए कहने पर साथियों ने उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने बताया कि सभी एक कॉलेज वाट्स एप ग्रुप का हिस्सा थे। उनमें से कुछ 21 जुलाई को हिंदी में मैसेज लिख रहे थे। तभी एक छात्र ने मराठी में लिखा, मराठी में बात करो नहीं तो राज ठाकरे आ जाएंगे। इसके बाद वाट्स एप ग्रुप में बहस होने लगी। अगले दिन सुबह करीब 10:30 बजे फैजान नाइक समेत चार छात्रों ने वाशों में कॉलेज के बाहर उस छात्र पर हमला कर दिया, जिसने मराठी में बोलने के लिए कहा था।

नाइक ने छात्र के सिर पर हॉकी स्टिक से भी वार किया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना के बाद एमएनएस ने हमलावर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एमएनएसप्रवक्ता गजानन काले ने कहा कि हम पीड़ित छात्र और उसके परिवार से मिले हैं। दोषियों को सजा मिलने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। यह घटना चेतावनी है कि महाराष्ट्र में बढ़ता भाषाई विभाजन खतरनाक है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने 16 जुलाई को मुंबई में एक दुकानदार के साथ मारपीट की।

भाजपा अध्यक्ष - यूपी भाजपा अध्यक्ष पद के लिए 6 नाम हुए शॉर्टलिस्ट

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) संगठन में बड़ा बदलाव करने जा रही है। मौजूदा यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल पूरा होने के बाद पार्टी नए चेहरे की तलाश में है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व को छह नामों की एक सूची भेजी गई है, जिसमें जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन का पूरा ध्यान रखा गया है। जल्द ही नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान होने की उम्मीद है।

पीएम मोदी की ट्रंप के साथ दोस्ती खोखली साबित हो रही है... जयराम रमेश का केंद्र सरकार पर तंज

नई दिल्ली। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए भारतीय कूटनीति की विफलता का आरोप लगाया और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री की दोस्ती खोखली साबित हो रही है। कांग्रेस (महासचिव) के संचार प्रभारी रमेश ने एक्स पर लिखा कि 19 जून, 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा चीन को क्लीन चिट देने की भारत को पहले ही भारी



कीमत चुकानी पड़ी है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी बहुप्रचारित दोस्ती अब खोखली साबित हो रही है। रमेश ने कहा कि भारतीय कूटनीति की घोर विफलता, खासकर पिछले दो महीनों में, चार तथ्यों से सबसे

ज्यादा उजागर होती है। ये तथ्य प्रधानमंत्री और उनके डोल पीटने वालों और जयजयकार करने वालों के बड़े-बड़े दावों की पोल खोलते हैं। 10 मई, 2025 से अब तक राष्ट्रपति ट्रंप 25 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया था। उन्होंने भारत और पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर उन्होंने युद्ध नहीं रोका, तो वे अमेरिका के साथ व्यापार समझौता नहीं करेंगे।

आर्मी चीफ बोले- ऑपरेशन सिंदूर से पाक को सीधा संदेश

नई दिल्ली। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की गई सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान को सीधा संदेश था कि आतंकवाद के समर्थकों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले का जवाब भी था, जो पूरे देश को गहरा घाव दे गया था। इस बार भारत ने हादसे पर शोक तो व्यक्त किया, साथ ही करारा जवाब भी दिया। जनरल द्विवेदी ने ये बातें लद्दाख के द्रास में कारगिल विजय दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहीं। उन्होंने कहा- दुश्मन को जवाब देना अब न्यू नॉर्मल है।

कारगिल विजय दिवस के 26 साल पूरे होने पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। उनके साथ तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। राजनाथ ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। 5 मई 1999 को पाकिस्तान की घुसपैठ के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की पहाड़ी चोटियों पर जंग हुई थी। युद्ध करीब 84 दिनों तक चला। 26 जुलाई 1999 को भारत की जीत के साथ युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ। इसमें भारतीय सैनिकों के बलिदान और वीरता को याद करते हुए हर साल 26 जुलाई को कारगिल

कारगिल के वीर सपूतों को याद कर भावुक हुए राष्ट्रपति-पीएम राष्ट्र ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर भारत ने उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध में असाधारण साहस का परिचय दिया और अपने प्राणों की आहुति दी। यह दिवस युद्ध में भारत की विजय का स्मरण कराता है और देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़ने वाले देश के सशस्त्र बलों के अदृष्ट संकल्प की याद दिलाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए देश के जवानों की असाधारण वीरता और दृढ़

निश्चय पर जोर दिया। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। यह दिवस हमारे जवानों की असाधारण वीरता, साहस एवं दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। देश के प्रति उनका समर्पण और सर्वोच्च बलिदान देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को बधाई दी और भारत के सशस्त्र बलों के अद्वितीय साहस

बिहार में पत्रकारों की बल्ले-बल्ले! मासिक पेंशन 6 हजार से बढ़कर 15 हजार हुई

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पत्रकारों की मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की। प्रात पत्रकारों को अब 15,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जो पहले 6,000 रुपये प्रति माह थी। इसके अलावा, इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले पत्रकार की मृत्यु होने पर, मृतक की पत्नी को आजीवन 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। पहले ऐसी महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह मिलते थे। इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित विभाग को निर्देश दे दिए हैं। इसको लेकर नीतीश ने एक्स पर

लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6 हजार रू? की जगह 15 हजार रू? पेंशन की राशि प्रदान करने का विभाग को निर्देश दिया है। साथ ही बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित पति/ पत्नी को जीवनपर्यन्त प्रतिमाह 3 हजार रुपये की जगह 10 हजार रुपये की पेंशन राशि दिए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि लोकतंत्र में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं

करगिल के शहीदों का साहस हमेशा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा-खरगे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को करगिल विजय दिवस पर सशस्त्र बलों के अदम्य साहस को सलाम किया और कहा कि शहीदों की वीरता एवं बलिदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। खरगे ने 'एक्स% पर पोस्ट किया, "करगिल विजय दिवस पर हम अपने सशस्त्र बलों के बहादुर सैनिकों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और सभी भारतीय नागरिकों को

हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम अपने शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं जिन्होंने करगिल युद्ध में बहादुरी से हमारी मातृभूमि की रक्षा की। उनका अदम्य साहस और वीरता पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 'एक्स पर पोस्ट किया, "करगिल विजय दिवस पर देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को शत-शत नमन और अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता

मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश हाईवे बंद



अशोकनगर के चंदेरी में राजघाट डैम के 12 गेट खोले गए। इससे यहां पुल पर 8 फीट तक पानी भर गया।

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला हाईवे बंद होने से वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हिमाचल

गजपति राजू ने गोवा के राज्यपाल पद की शपथ ली

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक गजपति राजू ने शनिवार को गोवा के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्होंने पी.एस. श्रीधरन पिछ्ई की जगह ली है। 74 साल के अशोक गजपति को राजभवन में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अराधे ने शपथ दिलाई। इस मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मौजूद रहे। अशोक गजपति की 14 जुलाई 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया था। शपथ लेने के बाद अशोक गजपति ने कहा कि वह जनता की सेवा करते हुए भारत के संविधान का पालन करेंगे। अशोक गजपति राजू गोवा के 20वें राज्यपाल बने हैं। वे इससे पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। वे 25 सालों से ज्यादा समय तक आंध्र प्रदेश राज्य विधानमंडल के सदस्य रहे और 13 सालों तक राज्य मंत्री रहे।



कारगिल विजय दिवस, देशवासियों के लिए है गौरव का उत्सव-मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल, एजेंसी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कारगिल विजय दिवस की बधाई देते हुए कहा है कि भारतीय सैनिकों ने पराक्रम की पराकाष्ठा करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पाकिस्तान को पराजित किया था। साठ दिन तक चलने वाले युद्ध की छवियां आज भी देशवासियों के मन मस्तिष्क पर बनी हुई है। भारतीय सैनिकों ने दुर्गम पहाड़ी परिस्थितियों में एक-एक चोटी को फतह कर अपने शौर्य का परचम फहराया, देश को गौरवान्वित किया और हमारा मनोबल बढ़ाया। हमें विश्वास है कि भारतीय सेना सभी चुनौतियों का सामना करने में सदैव समर्थ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शौर्य और बलिदान की अमर गाथा, कारगिल विजय दिवस हम सभी के लिए गौरव का उत्सव है। मां भारती के वीर सपूतों ने सर्वस्व न्यौछावर कर कारगिल में शत्रु का संहार कर विजय प्राप्त की। यह अवसर राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रण का है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया के माध्यम से जारी अपने संदेश में, प्रदेशवासियों से मां भारती की सेवा में सर्वस्व समर्पित करने का संकल्प लेने का आह्वान किया है।

हिन्दी फीचर फिल्म तन्वी द ग्रेट कर मुक्त

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फीचर फिल्म तन्वी द ग्रेट को कर मुक्त करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में राज्य शासन ने फिल्म को मध्यप्रदेश में कर मुक्त करने के आदेश जारी किए है।

फीचर फिल्म के मध्यप्रदेश में प्रदर्शन की अवधि 25 जुलाई से 23 अगस्त, 2025 तक के लिए मध्यप्रदेश मॉल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अधीन स्टेट जीएसटी की संपूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति करते हुए दर्शकों को छूट मिलेगी। फिल्म का निर्देशन मशहूर फिल्म अभिनेता श्री अनुपम खेर ने किया है।

संबंधित सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स द्वारा स्टेट जीएसटी की राशि को घटाकर दर्शकों को इस फिल्म के टिकट का विक्रय किया जाएगा। इस सेवा प्रदाय पर देय एवं भुगतान किये गये राज्य जीएसटी के अंश के बराबर की राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा सेवा प्रदाता को की जायेगी। फिल्म के प्रदर्शन के लिए संबंधित सिनेमाघरों मल्टीप्लेक्स के प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जाएगी। उल्लेखनीय है कि तन्वी द ग्रेट 21 वर्षीय तन्वी रैना की कहानी है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जुझते हुए अपने शहीद पिता के सपने को पूरा करने के लिए भारतीय सेना में शामिल होने का प्रयास करती है। इसकी संवेदनशील कहानी और सामाजिक संदेश को दर्शकों और समीक्षकों से व्यापक सराहना मिली है।

मैसूर में नगरीय निकायों के अध्यक्षों का हुआ प्रशिक्षण

भोपाल। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय नगरीय निकायों के अध्यक्षों के प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट का निरंतर आयोजन कर रहा है। हाल ही में प्रदेश के भोपाल, नर्मदापुरम और सागर संभाग के नगरीय निकायों के अध्यक्षों का प्रशिक्षण कर्नाटक के मैसूर में हुआ। जन-प्रतिनिधियों को नगरों के सुनिश्चित विकास एवं बेहतर राजस्व प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में 35 जन-प्रतिनिधि शामिल हुए। जन-प्रतिनिधियों को नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों से जुड़ी बेहतर सेवा व्यवस्था का अवलोकन कराया गया। इसके साथ ही नगरीय विकास से जुड़े विषय-विशेषणों ने प्रमुख विषयों पर व्याख्यान दिये। यह प्रशिक्षण सुदरलाल पट्टनायक राष्ट्रीय नगर प्रबंध संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया।

एमपी में बनेगी देश की पहली 3डी मॉडल गैलरी

भोपाल ,एजेंसी। भारत के मेडिकल इन्वोवेशन में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए एम्स भोपाल देश की पहली रोगी-विशिष्ट थ्रीडी मॉडल गैलरी बनाने की तैयारी कर रहा है। यह कदम न केवल मरीजों के इलाज को बेहतर बनाएगा, बल्कि मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों के लिए पढ़ाई और सर्जरी प्लानिंग को भी अत्याधुनिक बना देगा। एम्स भोपाल ने चिकित्सा क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत की है। संस्थान ने साल 2024 में एक हाईटेक %कम्प्यूटेशनल थ्रीडी मॉडलिंग एंड प्रिंटिंग लैब% की स्थापना की थी, जो अब देशभर में चर्चित हो चुकी है। इस लैब की सबसे बड़ी खासियत है - पालीजेट डिजिटल एनाटॉमी प्रिंटर,



हाई-पावर कंप्यूटर और विशेष सॉफ्टवेयर, जिनकी मदद से डॉक्टर मरीज के शरीर का ह्यूह थ्रीडी मॉडल तैयार कर सकते हैं। इस थ्रीडी प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल सर्जरी से पहले केस की गहराई से समझ, ऑपरेशन की प्लानिंग,

मेडिकल स्टूडेंट्स को रियल-लाइफ प्रैक्टिस और मरीजों को उनकी बीमारी को विजुअली समझाने के लिए किया जा रहा है। अब एम्स भोपाल भारत की पहली रोगी-विशिष्ट थ्रीडी मॉडल गैलरी बना रहा है, जिसमें विभिन्न जटिल बीमारियों के

मॉडल रखे जाएंगे। यह गैलरी डॉक्टरों, छात्रों और आम नागरिकों को शरीर की संरचना और बीमारियों की समझ विकसित करने में मदद करेगी। लैब से अब तक देश-विदेश के विशेषज्ञों का एक अंतरराष्ट्रीय सिम्पोजियम भी हो चुका है, जिसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साझा काम करने पर सहमति बनी थी। अब एम्स इस लैब के जरिए दो नए सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर रहा है, जिनमें से एक मैनिट भोपाल के साथ संयुक्त रूप से डिजाइन और मेडिकल मॉडलिंग पर आधारित होगा। भविष्य में पीएचडी की सुविधा भी मेडिकल और इंजीनियरिंग छात्रों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

एमपी में स्कूलों का हाल 5600 भवन जर्जर, 67 हजार में फर्नीचर और 15 हजार विद्यालयों में बिजली तक नहीं

भोपाल ,एजेंसी। मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। राज्य शिक्षा विभाग के हालिया आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश के हजारों स्कूल बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कहीं भवन जर्जर हैं तो कहीं बिजली, फर्नीचर और शौचालय की सुविधा नहीं है। इस बदहाल स्थिति ने न केवल छात्रों की शिक्षा पर असर डाला है बल्कि उनकी सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है। मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत बेहद खराब है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 92,032 सरकारी स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनमें से 5,600 स्कूलों के भवन पूरी



तरह जर्जर हैं और 81,568 क्लासरूम खस्ताहाल अवस्था में हैं। यह आंकड़े राज्य की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलते हैं। स्कूलों में न केवल संरचनात्मक कमी है, बल्कि बुनियादी सुविधाओं का भी गंभीर अभाव है। 15,651 स्कूलों में अब तक बिजली की सुविधा नहीं है, जबकि

67,034 स्कूलों में फर्नीचर की कमी है। इतना ही नहीं, 61,068 स्कूलों में प्रधानाध्यापक कक्ष भी मौजूद नहीं है। शौचालय की स्थिति भी बेहद खराब है। 2,787 स्कूलों में बालिका शौचालय ही नहीं है, और 9,833 स्कूलों में बालिका शौचालय कार्यरत नहीं हैं। बालकों के

लिए भी 3,116 स्कूलों में शौचालय नहीं हैं, जबकि 11,390 स्कूलों में ये निष्क्रिय हैं। 39,722 स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं है, जिससे सुरक्षा की स्थिति भी कमजोर हो जाती है। 4,978 स्कूलों में खेल मैदान तक उपलब्ध नहीं है, जो बच्चों की समग्र विकास प्रक्रिया को बाधित करता है। 647 स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है और 14,423 स्कूलों में हैंडवॉश यूनिट नहीं है, जिससे साफ-सफाई और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। भोपाल की ही बात करें तो यहां 858 सरकारी स्कूलों में से 120 में बिजली नहीं है, 44 में बालिका शौचालय नहीं है, और 464 स्कूलों में फर्नीचर की भारी कमी है।

प्रदेश में मिशन अंकुर के मैदानी कार्यकर्ताओं का दो वर्षीय कार्यकाल पूर्ण

भोपाल, एजेंसी। मध्यप्रदेश में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए संचालित मिशन अंकुर कार्यक्रम के कुशल संचालन के लिए अगस्त-2023 से जिलों में कार्यरत निपुण प्रोफेशनल्स फैलोज का विदाई समारोह शुक्रवार को भोपाल के राज्य शिक्षा केन्द्र में आयोजित हुआ। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री हरजिन्दर सिंह ने विगत दो वर्षों में एफएलएन फैलोज द्वारा जिलों में किये गये कार्यों के लिये धन्यवाद दिया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की सहयोगी संस्था सेंट्रल स्ववायर फाउंडेशन के साथ विभाग ने देश दुनिया के उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थानों से शिक्षित उर्जावान युवाओं को टीआईएसएस मुंबई के सहयोग से प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिशन अंकुर के कुशल संचालन के लिए तैनात किया था। इन युवा निपुण

प्रोफेशनल्स ने पिछले दो वर्षों में जिलों में अधिकारियों तथा शिक्षकों के साथ मिलकर कक्षा 1, 2 और 3 के बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निपुण प्रोफेशनल्स का मध्यप्रदेश के जिलों में दो वर्षीय कार्यकाल 31 जुलाई 2025 को पूरा हो रहा है। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र ने इन युवाओं द्वारा प्रदेश के नौनिहालों की शैक्षिक नींव को मजबूती प्रदान करने और किये गये कार्यों के लिये इन्हें प्रमाण-पत्र और स्मृति-चिन्ह भेंट किये। कार्यक्रम में 52 जिलों में कार्यरत सभी निपुण प्रोफेशनल्स के साथ ही सहयोगी संस्थाओं सेंट्रल स्ववायर फाउंडेशन की वरिष्ठ परियोजना लीडर सुश्री विशाखा तिवारी और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में अपर संचालक श्री राजीव तोमर ने मिशन अंकुर के बारे में जानकारी दी।



सतत प्रयासों से डिस्ट्रिक्ट टू ग्लोबल की ओर बढ़ता मध्यप्रदेश



भोपाल, एजेंसी। मध्यप्रदेश अब केवल निवेश प्रस्तावों का स्वागत करने वाला राज्य नहीं, बल्कि उद्योगों और उद्यमियों का भागीदार बन चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने एक नई कार्यसंस्कृति विकसित की है जहां नीतियों की घोषणा कागजों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ज़मीन पर उनके क्रियाव्ययन का वास्तविक प्रभाव दिखाता है। यही कारण है कि हाल के दिनों में उज्जैन, शाजापुर और इंदौर में आयोजित तीन विशिष्ट कार्यशालाएं इस प्रयास का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आई हैं। उज्जैन में आयोजित स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर केंद्रित कार्यशाला में बड़ी

संख्या में नए उद्यमियों, निवेशकों और स्टार्टअप प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सिंगल विंडो सिस्टम, ऑटोमैटिक अनुमतियाँ, ऑनलाइन एप्लिकेशन ट्रैकिंग और जन विश्वास अधिनियम जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। इस वर्कशॉप का मूल उद्देश्य यह संदेश देना था कि 'अब मध्यप्रदेश में उद्योग लगाना सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक सहज प्रक्रिया है।' मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा आरंभ किए गए स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज अभियान की चर्चा विशेष रूप से हुई, जिसमें 30 दिन के भीतर सभी औपचारिकताओं के साथ व्यवसाय शुरू करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। यह पहल उदाहरण में सराहना प्राप्त कर चुकी है और निवेशकों के बीच मध्यप्रदेश को एक भरोसेमंद गंतव्य के रूप में स्थापित कर रही है।

भोपाल, एजेंसी। स्कूल शिक्षा विभाग ने एजुकेशन पोर्टल की तर्ज पर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभाग की खेलकूद शाखा की गतिविधियों, प्रतियोगिता के आयोजन और उससे संबंधित पत्राचार को पेपरलेस कर दिया गया है। इस प्रक्रिया के चलते खेलों से जुड़ी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत मान्यता प्राप्त एमपी बोर्ड के विद्यालय, सीबीएसई के ऐसे स्कूल जो स्कूल गोम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के और स्कूल शिक्षा विभाग के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न खेलों की प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं वे इस पोर्टल पर

निश्चित पंजीयन शुल्क के साथ आवश्यक अभिलेख अपलोड करते हुए पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन 14 से 19 वर्ष से कम आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं के लिये एक ही बार कराना होगा। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम में प्रति वर्ष आवश्यकतानुसार अपग्रेड किये जाने की सुविधा प्रदाय की गई है। विद्यालय में अध्ययनरत नियमित खिलाड़ियों की दर्ज संख्या के मान से क्रीड़ा शुल्क का संकलन इसी पोर्टल के माध्यम से किये जाने की सुविधा दी गई है जो स्वतः ही संचालनालय, संयुक्त संचालक, संभाग एवं जिला शिक्षा अधिकारी के खाते में शासन द्वारा निर्धारित प्रतिशत के अनुसार अंतरित हो जाता है। यह व्यवस्था खेलों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और खिलाड़ियों की आयु के बारे में प्रमाणीकरण के साथ अपात्र खिलाड़ी को किसी भी स्तर पर प्रतियोगिता में शामिल होने से रोकता है। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को उच्च स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश में स्थित शासकीय विद्यालयों में 180 नोडल खेल केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों के माध्यम से खेल अधोसंरचना के साथ उत्कृष्ट स्तर की खेल सामग्री खेल प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पिछले वर्ष 500 खिलाड़ियों ने राज्य और संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागिता की और इसमें 600 पदक प्राप्त किये। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है।

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिया गया तकनीकी प्रशिक्षण

भोपाल, एजेंसी। भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष उपयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस प्रशिक्षण में विभाग के चारों वर्टिकल — पीडब्ल्यूडी (बी/आर), एमपीआरडीसी, एमपीबीडीसी तथा पीडब्ल्यूडी (भवन) — से कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंता और प्रमुख अभियंता स्तर के अधिकारी शामिल हुए। लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा भास्कराचार्य संस्थान के सहयोग से आई.टी. आधारित कई मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं इनमें सड़क निर्माण के साथ-साथ तालाब निर्माण के लिए उपयुक्त स्थानों का तकनीकी विश्लेषण कर सूची प्राप्त करने की व्यवस्था शामिल है। प्रशिक्षण में बताया गया कि हाल ही में वृक्षारोपण की



मॉनिटरिंग भी सैटेलाइट के माध्यम से की जाएगी, जिससे पर्यावरणीय कार्यक्रमों की पारदर्शिता और प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, सड़क निर्माण की परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए भी बीआईएसएजी-एन द्वारा एक विशेष तकनीकी मॉड्यूल विकसित किया गया है। अधिकारियों को यह भी बताया

गया कि विभाग की सभी संपत्तियों (असेट्स) को पीएम गतिशील पोर्टल पर किस प्रकार प्रभावी रूप से मैप किया जा सकता है। संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी दी कि भविष्य में परिक्षेत्रीय स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन कर सभी अधिकारियों को इन तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा

हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर में खोलने की तैयारी

भोपाल ,एजेंसी। एमबीबीएस की पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध कराने के बाद अब मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा जबलपुर में हिंदी का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने की तैयारी है। इसमें पढ़ाई से लेकर परीक्षा तक सब कुछ हिंदी में होगी। हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई कराने वाला यह देश का पहला मेडिकल कॉलेज होगा। मेडिकल यूनिवर्सिटी की शुक्रवार को हुई कार्यपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। अब इसका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) से अनुमति ली जाएगी। बैठक में तय किया गया है कि अभी एमबीबीएस की 50 सीटों के साथ 2027-28 के सत्र में कालेज प्रारंभ किया जाएगा। अस्पताल अलग

से नहीं बनाया जाएगा, बल्कि वर्तमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल को ही इस कॉलेज से संबद्ध किया जाएगा। मेडिकल विद्यार्थी अस्पताल में क्लीनिकल पढ़ाई कर सकेंगे। प्रयोग सफल होने पर सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रयास होंगे। मेडिकल से जुड़े दूसरे पाठ्यक्रम भी यहां हिंदी में शुरू किए जाएंगे। एमडी-एमएस की पढ़ाई भी आगे चलकर हिंदी में होगी। एमबीबीएस के पूरे पाठ्यक्रम में लगने वाली किताबें पहले से ही हिंदी में अनुवादित की जा चुकी हैं, इसलिए हिंदी में पुस्तक उपलब्ध कराने की समस्या भी नहीं आएगी। मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पुष्पराज सिंह बघेल ने बताया कि हिंदी में एमबीबीएस व अन्य पाठ्यक्रम के लिए प्रस्तावित मेडिकल कालेज देश में हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला पहला कालेज होगा।

एमपी ट्रांसको के सर्किल मुख्यालयों में हर माह होगी नॉलेज शेयरिंग वर्कशॉप

भोपाल। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) द्वारा अपने वृत्त यानि सर्किल स्तर के मुख्यालयों में प्रत्येक माह सभी संकायों के इंजीनियरों एवं लेखा अधिकारियों के लिए नॉलेज शेयरिंग वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। इन वर्कशॉप का उद्देश्य तकनीकी ज्ञान, अनुभव और कार्यप्रणाली को साझा कर परस्पर सीख की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसी क्रम में नॉलेज शेयरिंग वर्कशॉप का पहला सत्र गत दिवस प्रशासनिक भवन, बिजली नगर कॉलोनी गांवदिपुरा, भोपाल में संपन्न हुआ। पहले सत्र में अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री राजेश शांडिल्य द्वारा पावर कम्प्युनिकेशन, ओपीजीडब्ल्यू फोटे आदि तकनीकी विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं कार्यपालन अभियंता श्री अतुल नावर भी परीक्षण लाइनों, टॉवर, मोनोपोल इत्यादि से जुड़े अपने तकनीकी अनुभव साझा किए। वर्कशॉप में भोपाल मुख्यालय के अधिकारी, तकनीकी कर्मचारी सहित जबलपुर द्विवेदी और ट्रांसको के विभिन्न संकायों के अधिकारी-कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

6 दुकानें पर चला बुलडोजर, छज्जे-सीढ़ियां तोड़ी

वार्ड 8 और 11 में सड़क निर्माण रोके अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। वार्ड क्रमांक 8 और 11 में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में बाधा बन रहे अतिक्रमण पर शनिवार को नगर पंचायत प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए कार्रवाई की। स्थानीय ठेकेदार अभिमन्यु सिंह ने सीएमओ से शिकायत की थी कि निर्माण कार्य अवैध कब्जों के कारण रुक रहा है। इसके बाद दोपहर में नगर पंचायत ने बुलडोजर की मदद से अभियान चलाया, जिसमें कई दुकानों के छज्जे और सीढ़ियां तोड़ी गईं। कुल छह दुकानदारों के अतिक्रमण ढहाए गए। बताया गया कि कई लोगों ने सार्वजनिक नालियों पर सीधे निर्माण कर लिया था, जिससे जल निकासी बाधित हो रही थी और सड़क निर्माण



कार्य रुक गया था। कार्रवाई के दौरान 17 लोगों को नोटिस भी थमाए गए, जिनमें चेतावनी दी गई कि वे स्वयं

अवैध निर्माण हटा लें, अन्यथा अगली बार सीधे बुलडोजर चलेगा। अभियान के दौरान नगर पंचायत के मुख्य नगरपालिका अधिकारी रामावतार पटेल, नगर पंचायत अध्यक्ष मोनिका गुप्ता, उपयंत्री प्रफुल्ल गुप्ता और राजस्व निरीक्षक अशोक पटेल उपस्थित रहे। जिन लोगों के अतिक्रमण हटाए गए या जिन्हें नोटिस दिए गए, उनमें हरीशचंद्र गुप्ता, छोटेलाल गुप्ता, रघुनंदन सोनी, भूरेलाल केवट, शैलेन्द्र गुप्ता सहित 17 लोग शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा और निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

खेत में मिला शख्स का शव, टीआई बोले- गले पर खरोंच और नाक से खून के निशान, पीएम रिपोर्ट से होगा मौत का खुलासा

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। जिले के मोरवा थाना क्षेत्र के बरवानी गांव में एक व्यक्ति का शव गांव के ही एक खेत में मिला। मृतक की पहचान शिवकुमार कोल के रूप में हुई है। शव मिलने की सूचना मिलते ही मोरवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची।शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

गले पर हल्की खरोंच के निशान: थाना प्रभारी उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि शव गोरवी चौकी क्षेत्र के तहत मिला है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि मृतक के गले पर हल्की खरोंच के निशान हैं और नाक से खून भी निकला है। हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी।

घर से करीब 25-30 मीटर दूर खेत में मिला शव: परिजनों से बातचीत में पता चला कि शिवकुमार कोल रात 2 बजे तक घर पर ही थे।



सुबह जब घरवाले उठे तो वे घर से गायब थे। काफी खोजबीन के बाद दोपहर में उनका शव घर से करीब 25-30 मीटर दूर खेत में पड़ा मिला। टीआई ने बताया कि फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। यह हादसा है, बीमारी से मौत हुई या कुछ और ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा।

बमुरी स्कूल में 140 बच्चे दर्ज, 13 छात्र पढ़ने आए

डीईओ ने किया बचाव, कहा- बारिश की वजह से स्कूल में उपस्थिति कम

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले के मुख्यालय से किलोमीटर दूर बमुरी गांव का शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए छात्र नहीं आते हैं। स्कूल को 1 से 8 तक की मान्यता हासिल है। इस स्कूल में रजिस्टर पर 140 बच्चों के नाम दर्ज हैं। लेकिन केवल 13 छात्र ही स्कूल आते हैं।

पहली से पांचवी तक महज 5 बच्चे स्कूल आए: शनिवार को स्कूल का निरीक्षण करने पर केवल दो कक्षाएं चल रही थीं। पहली से पांचवीं कक्षा तक सिर्फ 4 बच्चे और छठवीं से आठवीं तक मात्र 7 बच्चे उपस्थित थे। स्कूल में 7 शिक्षक पदस्थ हैं। लेकिन उस दिन केवल तीन शिक्षक ही मौजूद थे।

लोगों का आरोप-हेडमास्टर नियमित रूप से स्कूल नहीं आते: धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे थे। अभिषेक मिश्रा उच्च कक्षाओं के सभी बच्चों को एक ही कमरे में पढ़ा रहे थे। हेडमास्टर सुखेंद्र सिंह चौहान कार्यालय में बैठे थे। स्थानीय



ग्रामीण राजभान सिंह और अन्य लोगों का आरोप है कि हेडमास्टर नियमित रूप से स्कूल नहीं आते। वे गैरहाजिर रहने वाले शिक्षकों से पैसे लेकर मामला दबा देते हैं। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

जिला शिक्षा अधिकारी बोले- बारिश की वजह से कम अटेंडेंस: इस क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से

ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं होती। शिक्षक इसका फायदा उठाकर अनुपस्थित रहते हैं। जब जिला शिक्षा अधिकारी पवन सिंह से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने शिक्षकों का बचाव किया। उनका कहना था कि बारिश के कारण उपस्थिति कम रही होगी। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि यह शिक्षा व्यवस्था के साथ मजाक है।

बल्कर ने बाइक को मारी टक्कर, घायल ग्रामीण अस्पताल में भर्ती; वाहन चालक मौके से भागा

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। देवनाढ़ इलाके में तेज रफ्तार बल्कर वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में ग्राम अमरपुर निवासी गोविंद सिंह घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गोविंद सिंह बाइक से सीधी शहर की ओर जा रहे थे। घटना शनिवार शाम करीब 4 बजे की है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक सवार गोविंद सिंह सड़क पर दूर जा गिरे और उन्हें चोटें आई हैं। टक्कर मारने के बाद बल्कर वाहन का चालक मौके से वाहन सहित फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही देवनाढ़ चौकी प्रभारी भूपेंद्र बागरी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घायल को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

फरार ट्रक चालक की तलाश कर रही पुलिस: चौकी प्रभारी भूपेंद्र बागरी ने बताया कि घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। इससे आरोपी वाहन



चालक की पहचान की जा सकेगी। पुलिस ने केस दर्ज कर वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय बृजेश पांडे, रजनीश सिंह बघेल और उत्तम विश्वकर्मा का कहना

है कि इस क्षेत्र में एनएच 39 पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार और लापरवाही आम हो गई है। इससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है।

बंदर ने एनसीएल कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी तोड़ी, बनारस रेफर; अमलोरी कॉलोनी में चार को काटा

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। जिले के नवानगर थाना क्षेत्र स्थित नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एननसीएल) की अमलोरी कॉलोनी में शनिवार दोपहर बंदर के हमले से एक कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी में फैंक्चर आया है। वहीं, एक ही दिन में कॉलोनी के चार लोगों को काट लिया। सूचना मिलते ही वन विभाग का उड़न दस्ता मौके पर पहुंचा। वन विभाग के एसडीओ एनके त्रिपाठी ने बताया कि स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद टीम को मौके पर भेजा गया है। बंदरों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है।

बंदर के हमले से एनसीएल कर्मचारी विनय सिंह गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बंदर के हमले से बचने के प्रयास में वे जमीन पर गिर गए। इससे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उन्हें उपचार के लिए बनारस रेफर किया गया है। एक अन्य घायल सुरेश यादव ने बताया कि पिछले दो-तीन दिनों से बंदरों का कॉलोनी में आतंक है। ये बंदर लोगों पर हमला करने के साथ घरों में भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज उन्हें भी बंदर ने पैर में काट लिया।

चारों तरफ घना जंगल: एसडीओ एनके त्रिपाठी का कहना है कि पूरा इलाका घने पेड़-पौधों से घिरा हुआ है। कॉलोनी के अंदर भी काफी पेड़-पौधे हैं। इसी वजह से बंदर आवासीय क्षेत्र में आ जाते हैं। वन विभाग की टीम बंदरों को खदेड़कर आवासीय परिसर से दूर भगाने का प्रयास कर रही है। अधिक समस्या होने पर बंदरों को रेस्क्यू करके पिंजरे में भरकर दूर जंगल में छोड़ा जाएगा।

गिद्ध संरक्षण को लेकर रीवा में आयोजित हुई एक दिवसीय कार्यशाला

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। वेटरनरी कॉलेज रीवा में गिद्ध संरक्षण को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के डीन डॉ. अजीत प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं में प्रकृति के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने में सहायक होते हैं। साथ ही, उन्होंने भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकता पर जोर दिया।

कार्यशाला में विशेषज्ञ के रूप में संजय टाइगर रिजर्व से बायोलाजिस्ट डॉ. संगीता केवट उपस्थित रहीं। उन्होंने गिद्धों की घटती संख्या के प्रमुख कारणों में से एक ह्रस्वदृष्ट (नॉन-स्टेरीयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स) दवाओं के दुष्प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने वेटरनरी छात्रों और डॉक्टरों को गिद्धों की विभिन्न प्रजातियों, उनके रहवास, पारिस्थितिकीय महत्व और संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया।

कार्यक्रम का आयोजन वेटरनरी कॉलेज रीवा के सहयोग से वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समन्वयन प्रोफेसर डॉ. अनिल सिंह ने किया जबकि संचालन प्रोफेसर



सुलोचना जी द्वारा किया गया। समग्र जन चेतना विकास परिषद के समन्वयक सुमित सिंह ने गिद्ध संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी, जागरूकता अभियान और युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और स्थानीय संगठनों द्वारा मिलकर कई

संरक्षण प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें जन-सहभागिता को प्रमुखता दी जा रही है। कार्यक्रम में कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्र, संस्था के सहयोगी चक्रपाणि मिश्रा, आरती पटेल, डॉ. संगीता सहित समस्त स्टाफ की उपस्थिति रही। वक्ताओं ने गिद्धों के पर्यावरणीय महत्व, उनकी

संख्या में हो रही गिरावट और जैविक संतुलन पर इसके प्रभाव पर गंभीर चर्चा की। कार्यशाला का उद्देश्य छात्रों में पर्यावरणीय चेतना जागृत करना, गिद्ध संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना और भविष्य के लिए एक संवेदनशील पीढ़ी तैयार करना रहा।

प्रेग्नेंट पत्नी को पीटा, गर्भ में बच्चे की मौत, बीच-बचाव करने आई मां की भी हत्या



मीडिया ऑडीटर, अनूपपुर (निप्र)। एक युवक ने अपनी गर्भवती पत्नी को पीटा। मां बीच बचाव करने आई तो आरोपी ने दोनों को एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। इसके बाद यहां खटिया की लकड़ी से जमकर मारपीट की। इसमें मां की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पत्नी के गर्भ में पल रहे 5 माह के बच्चे की भी जान चली गई। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के ताराडन गांव में शुक्रवार देर रात की है। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि आरोपी श्यामलाल का पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। मां नन बाई कोल (55) के बीच-बचाव करने पर आरोपी ने आपा खो दिया। इसके बाद दोनों पर जानलेवा हमला कर दिया।

गर्भवती पत्नी को जबरन शराब पीने को कहा: आरोपी श्यामलाल कोल अपनी पत्नी सरोज (28) को दारु पीने के लिए कह रहा था। पत्नी 5 माह की प्रेग्नेंट थी। उसने दारु पीने से मना कर दिया। इसके बाद नशे में श्यामलाल ने पत्नी से दारु पीने के लिए पैसे मांगे। पैसा नहीं देने पर पत्नी के साथ मारपीट करने लगा।

पत्नी शहडोल रेफर, हालत गंभीर: गंभीर रूप से घायल सरोज कोल को ग्रामीणों ने 108 एंबुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय अनूपपुर पहुंचाया। जहां उसके 5 माह के बच्चे की मौत होने पर हालत गंभीर हो गई। उसे बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज शहडोल रेफर किया है। जहां उसका इलाज चल रहा है। वह अभी भी बेहोशी की हालत में हैं।

हत्या के बाद वहीं बैठा रहा आरोपी: घटना की सूचना मिलते ही अनूपपुर एसडीओपी सुमित केरकेट्टा, कोतवाली प्रभारी अरविंद जैन और पुलिस दल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी श्यामलाल को घटनास्थल से ही हिरासत में ले लिया। आरोपी घटना के बाद भी वहीं बैठा हुआ मिला था। आरोपी के खिलाफ हत्या और गंभीर मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया है।

5 दिन पहले ही लौटा था घर: पड़ोसियों ने बताया है कि आरोपी श्यामलाल कोल शराब पीने का आदी है। पिछले पांच सालों से महाराष्ट्र में रहकर मजदूरी कर रहा था और 5 दिन पहले ही वापस ग्राम ताराडन में अपने घर लौटकर आया था।

सरोज से की थी दूसरी शादी: श्यामलाल कोल की पहली शादी 3 साल पहले अनूपपुर जिले के चित्तहारी गांव में हुई थी। लड़ाई झगडा और शराब की विवाद में पहली पत्नी में श्यामलाल कोल को छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद श्यामलाल कोल ने 2024 में सरोज कोल से शादी कर ली थी।

प्राथमिक विद्यालय में छत का प्लास्टर गिरा, कक्षा में 33 बच्चे थे; शिक्षकों ने पहले ही दी थी चेतावनी



मीडिया ऑडीटर, शहडोल (निप्र)। शहडोल जिले के बोडरी ग्राम पंचायत के सेहराटोला में स्थित शासकीय स्कूल की छत का एक बड़ा हिस्सा शुक्रवार को अचानक टूटकर गिर गया। घटना के समय कमरे में बच्चे और शिक्षक मौजूद थे। गनीमत रही किसी बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई। इस घटना का वीडियो शनिवार को सामने आया है। यह विद्यालय भवन 1999-2000 में बना था और अब लगभग 25 वर्ष पुराना हो चुका है। वर्तमान में कक्षा एक से पांचवीं तक के 33 बच्चे यहां पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले साल शिक्षकों ने छत में आई दरारों की मरम्मत कराई थी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को लिखित रूप में चेतावनी भी दी थी कि जर्जर भवन से कभी भी हादसा हो सकता है। इसके बावजूद न तो कोई ठोस मरम्मत कार्य हुआ और न ही नए भवन के निर्माण के लिए कदम उठाए गए।

विभाग ने नहीं दिया ध्यान: शिक्षक अमर पटेल ने कहा कि हमने पिछले साल ही चेतावनी दी थी कि यह भवन सुरक्षित नहीं है। हमें उम्मीद थी कि विभाग इस पर ध्यान देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।" कक्षा में मौजूद बच्चों के माता-पिता भी इस घटना के बाद चिंतित हैं। एक अभिभावक ने बताया कि "हम अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। स्कूल प्रशासन को इस मुद्दे की गंभीरता से लेना चाहिए।"

निजी मकान में लगेगे कक्षाएं: बीआरसी सोहागपुर के महेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि इस घटना की जानकारी हमें मिली है और हम आवश्यक कदम उठाएंगे। हमारे निर्देश हैं कि जर्जर भवनों की कक्षाएं सुरक्षित निजी स्थानों पर संचालित की जाएं। शिक्षा विभाग ने अब हालात को गंभीरता से लेते हुए कक्षाओं को एक निजी मकान में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।

मंदिर से सोने-चांदी की आखें और पायल चोरी, पुलिस को अब तक नहीं मिला चोरों का सुराग

मीडिया ऑडीटर, सीधी शिकायतकर्ता रश्मि सिंह ने (निप्र)। जिले के चुरहट थाना क्षेत्र के पुराने मां काली मंदिर से चोरों ने सोने की दो आखें, चांदी की दो आखें और चांदी की पायल चोरी कर ली हैं। यह घटना चुरहट थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर पास थी और उन्होंने बिना शक जुलाई की सुबह हुई।

शिकायतकर्ता रश्मि सिंह ने बताया है कि सुबह करीब 9 बजे दो अज्ञात व्यक्ति उनके घर आए। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति पर मां काली आ गई हैं और तुरंत मंदिर में पूजा करनी है। मंदिर की चाबी रश्मि के पास थी और उन्होंने बिना शक 9 घण्टे की चुरहट में पकड़े हुए चोरी की सुबह हुई।

संपादकीय

चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों के फैलाव का संकट

विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो चिकनगुनिया अब विकराल रुप लेता जा रहा है। एक मोटे अनुमान के अनुसार आने वाले समय में पांच अरब लोगों के इसके दायरें में आने की पूरी पूरी संभावना है। हालांकि चिकनगुनिया से मौत का आंकड़ा प्रभावितों में से केवल एक प्रतिशत है पर जिस तरह से इसके फैलने की संभावनाएं बनती जा रही है निश्चित रुप से मौत का आंकड़ा भी बढ़ेगा और लाख दावों के बावजूद इसके स्वास्थ्य पर दूरगामी गंभीर प्रभाव भी पड़ेगा। चिकनगुनिया की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय अफ्रीका से एशिया को लपेटे में लेने वाली यह बीमारी अब योरोप को भी अपनी जद में करीब करीब ले चुकी है। दरअसल जलवायु परिवर्तन भी इसके फैलाव में सहायक है। तापमान बढ़ोतरी और नमी दोनों के कारण चिकनगुनिया का मच्छर फैलता है। जहां पानी जमा हुआ इसके मच्छर को डेरा जमाने का अवसर मिल जाता है। दुनिया के 119 देशों में चिकनगुनिया अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। हमारे देश में तो पिछले कुछ वर्षों से चिकनगुनिया लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा ही रहा है। यदि हमारे देश भारत की बात करें तो गत वर्ष चिकनगुनिया के दो लाख संदिग्ध मामलें सामने आये थे जिनमें से 17 हजार से अधिक मामलों में चिकनगुनिया की पुष्टि हुई थीं। भले ही यह संख्या कम लग रही हो पर जिस तरह से चिकनगुनिया हमारे देश सहित दुनिया के देशों में पांव पसार रहा है यही विश्व स्वास्थ्य संगठन की चिंता का प्रमुख कारण है। चिकनगुनिया की जहां तक पहचान की बात है तो माना जाता है कि तंजानिया में 1952 में चिकनगुनिया का नामकरण हुआ। दरअसल माकोंडे में पठार में चिकनगुनिया के मरीज को पहचान हुई। चिकनगुनिया में बुखार तो होता ही है पर यह सबसे अधिक प्रभावित जोड़ों को करता है। चिकनगुनिया में जोड़ो में भयंकर दर्द होता है और यह दर्द आसानी से व जल्दी जाता भी नहीं है। मकोंडे भाषा में चिकनगुनिया का मतलब दोहरा कर देना है और चिकनगुनिया के लक्षण दर्द के मारे दोहरा कर देने के कारण इसे चिकनगुनिया कहा जाने लगां। तंजानिया के दो वैज्ञानिकों मैरियन राबिन्सन और डब्ल्यूएचआर लम्सडेन ने 1955 में दो अलग अलग शोधपत्र लिखकर इसके बारे में जानकारी दी। जहां तक भारत की बात है तो 1963 में कोलकता में चिकनगुनिया से पीड़ित मरीज पाया गया। चिकनगुनिया में बुखार तो सामान्यतः दो से 5 दिन रहता है पर जोड़ों का दर्द लंबे समय तक असर दिखाता है। चिकनगुनिया मच्छर जनीत बीमारी है और पिछले कुछ सालों खासतौर से जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरुप मच्छर जनीत रोगों अधिक फैलाव हुआ है और पहले बरसात के पानी जमा होने के कारण फैलने वाली यह बीमारी अब गर्मी के मौसम बल्कि यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी छट-बारह महीने अपना असर दिखाने लगी है। इस साल हमारे यहां मानसून ने समय से पूर्व प्रवेश किया है और राजस्थान ही नहीं अपितु देश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बरसात हो रही हैं। जिस तरह की हमारी ड्रेनेज व्यवस्था है और जिस तरह से जल भराव के हालात हो रहे हैं उससे चिकनगुनिया का प्रकोप व्यापक रुप से देखने को मिल सकता है। अल्फाविषाणु परिवार के इस सदस्य एडिस के लावा के फैलाव को रोकने के लिए फोगिंग की प्रभावी व्यवस्था तो अभी दिखाई नहीं देती। फिर पानी का जमाव, गंदगी और बातावरण की नमी व लगातार बरसात के चलते मच्छरों का प्रकोप बढ़ेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दरअसल हम आपदा से निपटने के लिए पहले से तैयार रहते ही नहीं है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर तो पानी का भराव, किचड़, गंदगी आदि तो है ही इसके साथ ही हमारी प्रवृति के अनुसार हम स्वयं मच्छर जनित बीमारियों को फैलने से रोकने के स्थान पर उसके फैलाव में सहभागी बन जाते हैं।

भारत एवं यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौते से बढ़ेगा विदेशी व्यापार

प्रह्लाद सबनानी

दिनांक 24 जुलाई 2025 को भारत एवं यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं यूके के प्रधानमंत्री श्री कीर स्टारमर की उपस्थिति में सपन्न हो गया। यूके के यूरोपीयन यूनियन से अलग होने के बाद यूके का भारत के साथ यह द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता यूके के इतिहास में सबसे बड़ा द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता कहा जा रहा है। इस द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते के सपन्न होने के बाद भारत एवं यूके के बीच विदेशी व्यापार में अतुलनीय वृद्धि की सभावना व्यक्त की जा रही है। यूके ने हाल ही में अमेरिका के साथ भी एक व्यापार समझौता सपन्न किया है परंतु यूके के प्रधानमंत्री भारत के साथ संपन्न किए गए द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते को उससे भी बड़ी डील बता रहे हैं।



अमेरिका एक ओर जहां विभिन्न देशों के साथ टैरिफ युद्ध की घोषणा कर रहा है एवं अन्य देशों से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर भारी भरकम टैरिफ लगा रहा हैं वहीं भारत एवं यूके के बीच द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत टैरिफ की दरों को कम किया जाकर शून्य के स्तर पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अतः यह द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता विश्व के अन्य देशों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत सामान्यतः दो देशों के बीच होने वाले विदेशी व्यापार पर टैरिफ की दरों को कम किया जाता है अथवा शून्य के स्तर तक लाया जाता है ताकि इन दोनों देशों के बीच विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। इसी सिद्धांत के अंतर्गत भारत को जिन क्षेत्रों में लाभ हो सके, इनमें फूटवोयर उद्योग, लेदर उद्योग, टेक्स्टायल उद्योग, इंजीनीयरिंग उद्योग एवं जेम्स एवं ज्वेलरी उद्योग शामिल हैं। इसी प्रकार यूके को जिन क्षेत्रों में लाभ हो सकता है, इनमे विस्की, कार, चोकलेट, बिस्किट, कास्मेटिक, आदि उत्पाद निर्मित करने वाले उद्योग शामिल हैं। साथ ही, यूके को उम्मीद है कि भारत एवं यूके के बीच सम्पन्न हुए इस द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते से 800 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश भारतीय कम्पनियों द्वारा यूके में किया जा सकता है। यह यूके के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यूके में रोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे।

वर्तमान में भारत एवं यूके के बीच 56,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी व्यापार प्रतिवर्ष होता है। उक्त द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते के सम्पन्न होने के बाद भारत एवं यूके के बीच 34,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष का विदेशी व्यापार बढ़ सकता है। वर्ष 2030 तक भारत एवं यूके के बीच विदेशी व्यापार को 120,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष के स्तर तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके बाद वर्ष 2040 तक दोनों देशों के बीच विदेशी व्यापार को 160,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर तक ले जाया जा सकेगा। भारत से यूके को निर्यात होने वाले लगभग 99 प्रतिशत पदार्थों पर यूके द्वारा टैरिफ की दर को शून्य किया जा रहा है। इसी प्रकार, भारत द्वारा भी यूके से आयात किए जाने वाले 64 प्रतिशत पदार्थों पर टैरिफ की दर को शून्य किया जा रहा है। वर्तमान में भारत में यूके से आयात होने वाले पदार्थों पर औसत टैरिफ दर 15 प्रतिशत है, इसे घटाकर 3 प्रतिशत किया जा रहा है। दोनों देशों द्वारा एक दूसरे से विभिन्न पदार्थों के होने वाले विदेशी व्यापार पर टैरिफ की दरें कम करने से दोनों देशों में एक दूसरे से आयात किया जाने वाले उत्पाद सस्ते हों जाएंगे। उत्पाद सस्ते होने से उनकी बाजार में मांग बढ़ेगी, इन उत्पादों की मांग बढ़ने से उनका उत्पादन बढ़ेगा जो अंततः रोजगार के नए अवसर निर्मित करेगा। अतः इस द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों को ही लाभ

होने जा रहा है। भारत के जेम्स एवं ज्वेलरी उद्योग से प्रतिवर्ष यूके को होने वाले निर्यात, आगामी दो वर्षों में दुगने होकर 250 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। टेक्स्टायल उद्योग के मामले में भारत के उत्पादों को वियतनाम एवं बांग्लादेश के साथ गला काट प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। परंतु, अब भारत के उत्पादों पर टैरिफ की दरें कम अथवा शून्य होने से भारत के उत्पाद यूके में प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे। यूके में कुल आयात होने वाले गारमेंट्स में भारत की हिस्सेदारी केवल 6 प्रतिशत है जो अब आगामी वर्षों में दुगनी होकर 12 प्रतिशत होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। भारत के इंजीनीयरिंग उद्योग को इस मुक्त व्यापार समझौते से अत्यधिक लाभ हो सकता है और भारत के इस क्षेत्र से यूके को निर्यात, वर्ष 2030 तक दुगने होकर 750 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंच जाने की सम्भावना है। समुद्रीय खाद्य उत्पाद के क्षेत्र में भी भारत से यूके को निर्यात जो अभी केवल 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर के हैं, दुगने होकर 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर सकते हैं। अभी यूके में समुद्रीय खाद्य पदार्थों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी केवल 3 प्रतिशत की है। लेदर उद्योग से होने वाले भारत से आयात पर भी टैरिफ की दर को यूके में शून्य किया जा रहा है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उक्त वर्णित समस्त क्षेत्र/उद्योग भारत में श्रम आधारित उद्योग हैं। अतः इन क्षेत्रों से निर्यात बढ़ने पर भारत में इन क्षेत्रों में रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित होंगे। इन क्षेत्रों से होने वाले उत्पादों पर द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत यूके द्वारा टैरिफ की दर को शून्य करने पश्चात यूके में यह पदार्थ सस्ते होंगे इससे यूके में इन पदार्थों की मांग तेजी से बढ़ेगी और भारतीय कम्पनियों के यूके को इन पदार्थों के निर्यात बढ़ेंगे। इससे भारतीय कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करनी होगी, जिससे भारत में रोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे। भारत में यूके से आयात किए जाने वाले पदार्थ, जिन पर भारत द्वारा आयात कर में कमी की जाने वाली हैं, उनमें शामिल हैं- स्कोच विस्की जिस पर टैरिफ की दरों को 150 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत किया जा रहा है। यूके में निर्मित कारों के आयात पर अभी भारत द्वारा 110 प्रतिशत का टैरिफ लगाया जा रहा है, इसे घटाकर आगे आने वाले 5 वर्षों में 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इसी प्रकार ब्रिटेन में निर्मित चोकलेट, बिस्किट एवं कास्मेटिक उत्पादों पर भी आयात करों में कमी होने से यह उत्पाद भारत में सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगे। भारत में कृषकों के हितों का ध्यान रखते हुए डेयरी, तेल एवं फलों आदि जैसे कृषि पदार्थों को इस मुक्त व्यापार समझौते से बाहर रखा गया है। भारत से यूके को अभी 1450 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निर्यात प्रतिवर्ष होता है, यह यूके के कुल आयात का केवल 1.8 प्रतिशत है। इस प्रकार, अभी भारत से यूके को निर्यात बहुत कम मात्रा में होता है। वर्तमान में भारत द्वारा सबसे अधिक मात्रा में निर्यात, 200 करोड़ अमेरिकी डॉलर का, पेट्रोलियम उत्पादों का किया जा रहा है। फार्मा सेक्टर से भी यूके को केवल 85 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया जा रहा है, जो यूके के कुल आयात का केवल 2.8 प्रतिशत है। इस प्रकार भारत को उक्त विभिन्न क्षेत्रों में यूके के रूप में एक बहुत बड़ा बाजार मिल रहा है। केमिकल, आयरन एवं स्टील, फूटवेयर, रबर, आदि भी ऐसे क्षेत्र/उद्योग हैं जिनसे भारत से यूके को बहुत कम मात्रा में निर्यात किया जाता है। भारत के लिए यह समस्त उद्योग अहम हैं क्योंकि इन क्षेत्रों/उद्योगों में रोजगार के अवसर निर्मित करने की अपार सम्भावनाएं मौजूद हैं। यूके के कुल आयात में भारत का मार्केट शेयर बहुत कम है। भारतीय व्यापार को अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा और भारत में निर्मित उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना होगा ताकि इनके निर्यात को बढ़ाया जा सके। अमेरिका के ट्रम्प प्रशासन द्वारा लगातार विभिन्न देशों के साथ टैरिफ युद्ध की घोषणा के बीच विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, भारत एवं यूके ने आपस में द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते को सम्पन्न कर पूरे विश्व को राह दिखाई है कि किस प्रकार एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखकर विदेश व्यापार किया जा सकता है।

शोध अध्ययन भी बता रहे विशेष गहन पुनरीक्षण की जरूरत

उमेश चतुर्वेदी बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण पर विपक्षी दलों की ओर से सवाल न ही उठता तो हैरत होती। यह ठीक है कि चुनाव आयोग ने अपने 24 जून के इस संदर्भ में दिए गए आदेश में बार-बार बदलाव किया है,लेकिन विपक्षी खेम की ओर से इस पुनरीक्षण पर सवाल उठने की वजह उनकी आशंका है। उन्हें लगता है कि इस पुनरीक्षण के बहाने उनके वोट बैंक को सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और जेडीयू के इशारे पर चुनाव आयोग काट देगा। उनकी आशंका पर चर्चा से पहले एक हालिया शोध का भी जिक्र किया जाना जरूरी है, जिसके अनुसार बिहार में करीब 77 लाख फर्जी वोटर हैं। ये वोटर अल्पसंख्यक वर्ग वाले सिर्फ विदेशी घुसपैठिये ही नहीं हैं, बल्कि इसमें मृत और अपनी रियायश छोड़ चुके मतदाता भी हैं। डेमोग्राफिक रिकंस्ट्रक्शन एंड इलेक्टोरल रोल इम्प्लेशन, एस्टीमेटिंग दी लैजिटिमेंट वोटर बेस इन बिहार, इंडिया नाम शोध अध्ययन के मुताबिक बिहार की मतदाता सूची में ही ऐसी गड़बड़ियां नहीं हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि ऐसी गड़बड़ियां बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश की मतदाता सूची में हो सकती है। इस शोध अध्ययन को मुंबई के एस्पीजी जैन इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर विधु शेखर और और आईआईएम, विशाखापत्तनम के असिस्टेंट प्रोफेसर मिलन कुमार ने मिल कर किया है। एसएसआरएन में प्रकाशित यह अध्ययन किसी अनुमान पर नहीं, बल्कि सरकारी आंकड़ों, मसलन राज्य की जन्म और मृत्यु दर के साथ ही राज्य से हुए पलायन और आयु प्रत्याशा के सरकारी आंकड़ों के गहन अध्ययन और विश्लेषण पर आधारित है। विधु शेखर और मिलन कुमार के अध्ययन के मुताबिक, बिहार में इस समय करीब सात करोड़



89 लाख वोटरों का नाम मतदाता सूची में दर्ज है। इस अध्ययन के मुताबिक, इनमें से करीब 77 हजार नाम फर्जी हैं। यानी ये मतदाता या तो मर चुके हैं या बरसों पहले से अपनी बताई या दर्ज जगह से पलायन करके कहीं और जा बसे हैं। फर्जी या गलत मतदाताओं का यह आंकड़ा करीब 9.7 प्रतिशत होता है। इसका मतलब यह हुआ कि करीब दस प्रतिशत मतदाता ज्यादा हैं या असल में हैं ही नहीं। विधु शेखर और मिलन कुमार अपने शोध के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि राज्य की हर विधानसभा सीट पर करीब तीस हजार मतदाताओं का नाम गलत तरीके से दर्ज है। बिहार में विधानसभा की

243 सीटें हैं। विधानसभाओं में कुछ सौ मतदाताओं का अंतर ही जीत-हार पर असर डाल देता है। साल 2020 के विधानसभा चुनावों में करीब बीस प्रतिशत सीटों पर जीत और हार का अंतर महज ढाई फीसद तक ही था। इनमें से 17 सीटों पर जीत तो एक प्रतिशत के कम वोट से ही हुई थी। विधु शेखर और मिलन कुमार को आशंका है कि अगर गहन पुनरीक्षण में इन मतदाताओं के नाम नहीं काटे गए तो उनके नाम पर चुनावी नतीजों को बदला जा सकता है। इस अध्ययन के अनुसार, बिहार के गांवों में जहां मृत्यु के आंकड़े अपडेट ना होने की वजह से

फर्जी नाम ज्यादा हैं, वहीं शहरी इलाकों में पलायन के बावजूद नाम काटे नहीं गए हैं। राज्य में पिछली बार मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 2003 में हुआ था। उस समय राज्य में करीब तीन करोड़ 41 लाख मतदाता थे। राज्य की मौजूदा जन्म और मृत्यु दर के हिसाब से इसके बाद 4.83 जुड़ने चाहिए थे। इसके साथ ही सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन वर्षों में राज्य से करीब एक करोड़ 12 लाख वोटरों ने पलायन किया है। उन्होंने अपना स्थायी ठिकाना राज्य से बाहर बना लिया है। इसे दिल्ली, मुंबई, पंजाब जैसे शहरों और राज्यों में देखा भी जा रहा है, जहां भारी संख्या में बिहारी मूल के मतदाता हैं। इस शोध अध्ययन के मुताबिक, पुराने वोटरों, जन्म-मृत्यु दर की गणना और पलायन के बाद के आंकड़ों को मिलाकर राज्य में असल मतदाताओं की संख्या सात करोड़ 12 लाख के ही आसपास ही बैठती है। इस लिहाज से कह सकते हैं कि राज्य में जो सतहत्तर लाख ज्यादा वोटरों के नाम हैं, वे इन वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर गड़बड़ हैं। विधु शेखर और मिलन कुमार के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए राज्य में आधार कार्ड की उपलब्धता को भी जोड़ा जा सकता है। यह भी राज्य में फर्जी वोटरों की ओर इशारा करता है। वैसे मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड को वैध प्रमाण पत्र माना जाता है। लेकिन इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारी संख्या में फर्जी राशन कार्ड हो सकते हैं या आधार कार्ड भी बन सकते हैं। राज्य के सीमांचल के जिले मसलन अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिलों में मुस्लिम आबादी करीब 39 से लेकर 68 प्रतिशत तक है,लेकिन इनकी सीमाएं पश्चिम बंगाल और नेपाल से जुड़ी हैं। पश्चिम बंगाल के सीमांचल के नजदीकी जिले बांग्लादेश से सटे हैं। इसकी वजह से इस इलाके में घुसपैठ का भी

आरोप लगाता रहा है। बिहार सरकार द्वारा जाति-आधारित सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो इस आरोप में दम नजर आता है। इस आंकड़े के मुताबिक, राज्य का औसत आधार कवरेज लगभग 94 प्रतिशत है, जबकि 68 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज में कुल जनसंख्या से करीब 105.16 प्रतिशत आधार है। इसी तरह, कटिहार में 45 प्रतिशत और अररिया में 50 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहां आधार कुल जनसंख्या का करीब 101.92 और 102.23 प्रतिशत ज्यादा है। सीमांचल के ही जिले पूर्णिया में 39 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहां आधार कुल जनसंख्या का 101 प्रतिशत है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि सीमांचल हर 100 निवासी पर 120 से अधिक आधार कार्ड हैं। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में इन जिलों में मतदाता सूची में नाम के सत्यापन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्य नहीं माना है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मिले अधिकारों के तहत चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधान मंडलों का चुनाव करता है। इसके लिए उसे जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत मतदाता सूची बनाने और उसे अद्यतन करने का अधिकार मिला है। स्वच्छ लोकतंत्र के लिए जरूरी स्वच्छ और स्पष्ट मतदाता सूची है। चुनाव आयोग का यह वैधानिक दायित्व है कि फर्जी वोटरों को मतदाता सूची से बाहर करे। लेकिन आज की राजनीति अपने वोटरों को साधने तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि अपने प्रतिबद्ध वोटरों की रक्षा करने की हो गई है। बिहार में माना जाता है कि एन वाई समीकरण यानी मुस्लिम और यादव वोटर राष्ट्रीय जनता दल का समर्थक है।

बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग-रनवे का विस्तार अटका, केन्द्र-राज्य को लगाई फटकार

हाईकोर्ट ने कहा- बोलिए हमसे नहीं हो पाएगा, मुख्य सचिव-रक्षा सचिव से मांगा शपथ-पत्र

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (निप्र)। बिलासा देवी एयरपोर्ट में सुविधाएं बढ़ाने को लेकर केंद्र-राज्य सरकार के सुस्त रवैये पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि आप स्टेटमेंट दे दीजिए कि सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, हम पीआईएल खत्म कर देते हैं। बिलासपुर का भाग्य कभी तो जागेगा।वता दें कि एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग, रनवे का विस्तार होना है। राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। लेकिन मामला केंद्र में अटका है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि रक्षा मंत्रालय जमीन के बदले ज्यादा रकम की मांग कर रहा है, जबकि सरकार चाहती है कि पहले जमीन उसके नाम हो, तभी आगे का काम शुरू किया जाए।

यहां अटका है काम: साल 2023 में रनवे विस्तार के लिए तत्कालीन सरकार ने सेना की जमीन वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। जमीन के एवज में रक्षा मंत्रालय को 90 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया था। केवल केंद्र सरकार से जमीन वापसी के लिए औपचारिक सहमति देना बाकी रह गया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ।

साल 2025 में 286 एकड़ जमीन पर रनवे बढ़ाने वर्तमान की राज्य सरकार ने अनुमति दे



दी है। लेकिन सरकार ने कोर्ट में ये बताया है कि रक्षा मंत्रालय जमीन के बदले ज्यादा रकम की मांग कर रहा है, जबकि राज्य सरकार चाहती है कि पहले जमीन उसके नाम हो, तभी आगे का काम शुरू किया जाए।

जानिए कोर्ट रूम से लाइव...चीफ जस्टिस क्यों हुए नाराज: केस की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब में कुछ फोटोग्राफ्स पेश किए। साथ ही दावा किया कि एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग से जुड़े कार्य प्रगति पर हैं। लेकिन, तस्वीरें देखकर चीफ जस्टिस सिन्हा भड़क गए। उन्होंने सख्ती दिखाते हुए कहा कि- क्या दिख रहा है इन तस्वीरों में एक

गाड़ी खड़ी है, पीछे दो-चार लोग खड़े हैं। काम कहाँ हो रहा है? जरा हमें भी दिखाइए।

चीफ जस्टिस बोले- कभी तो जागेगा बिलासपुर का भाग्य: चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कोर्ट में स्पष्ट कहा- हर बार सुनवाई पर समय मांगा जाता है। लेकिन, जमीनी हकीकत कुछ और है। समय मांगने के बाद भी कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि अफसरों की बाड़ी लेंग्वेज देखकर ही लगता है कि उन्हें काम करने की कोई इच्छा नहीं है। लगता है जब नई सरकार आएगी, तब शायद बिलासपुर का भाग्य जगेगा।

डिफेंस ने दे दी थी मंजूरी, फिर क्यों अटका काम: याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि रक्षा मंत्रालय पहले ही 286 एकड़ जमीन पर रनवे विस्तार और अन्य कार्यों की अनुमति राज्य सरकार को दे चुका है। इस पर कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि जब अनुमति मिल गई, तो अब क्या दिक्कत है?

इस पर बताया गया कि रक्षा मंत्रालय जमीन के बदले ज्यादा रकम की मांग कर रहा है, जबकि राज्य सरकार चाहती है कि पहले जमीन उसके नाम हो, तभी आगे का काम शुरू किया जाए।

कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी से मांगा जवाब: एडवोकेट प्रफुल्ल एन भारत ने कोर्ट को बताया कि जमीन के एवज में रक्षा मंत्रालय ने अधिक राशि की मांग की है, जिसे लेकर मामला अटका हुआ है। राज्य सरकार पहले जमीन अपने नाम कराना चाहती है, उसके बाद आगे कार्य शुरू होगा।

कोर्ट ने ये भी कहा कि राज्य और केंद्र दोनों जगह आपकी ही सरकार है, फिर भी यह हाल है। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और रक्षा सचिव को तलब किया है और उनसे शपथ-पत्र सहित डिटेल जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है।

दोस्त के साथ मिलकर की चोरी शराब दुकान के आसपास नशेड़ियों की गाड़ी करते थे टारगेट, 3 बाइक बरामद

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। नाबालिग ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बाइक चोरी की वारदात की है। दोनों आरोपी शराब दुकान के पास खड़ी नशेड़ियों की बाइक को टारगेट करते थे। इन्होंने माना इलाके में अलग-अलग जगहों से 3 बाइक चोरी की थी। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक नाबालिग है।

माना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि 2 लोग अपने पास बाइक रखे हैं और बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। पूछताछ में एक ने अपना नाम दिनेश पाल निवासी अभनपुर रायपुर बताया और दूसरा नाबालिग था। आरोपियों से जब गाड़ी के कागजात मांगे गए तो वह गुमराह करने लगे।

पुलिस की कड़ाई से पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि माना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बनरसी स्थित शराब दुकान के पास से बाइक चुराई गई थी। चोरी की अन्य वाहनों के संबंध में पूछताछ करने पर उन्होंने माना के अलग-अलग क्षेत्र से अन्य 2 दोपहिया वाहनों को भी चोरी करना कबूल किया। बरामद बाइक की कीमत 1 लाख 20 हजार है।

आज को होगी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा, जिले के 8 परीक्षा केंद्रों में 2 हजार से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले में आगामी 27 जुलाई को आयोजित होने वाली छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) की आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में शुक्रवार को जिला सभा कक्ष में कलेक्टर जी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में परीक्षा से जुड़े सभी पर्यवेक्षकों और उद्घनदस्ता दल के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कलेक्टर ने व्यापम के दिशा-निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा कि परीक्षा के सुचारु संचालन के लिए जिले में 08 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 2042 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा, निगरानी और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 08 आब्जर्वर, 03 रिजर्व टीम, उद्घनदस्ता टीम 01 तथा उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को जिला पुलिस नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इन शिक्षण संस्थानों को बनाया गया है परीक्षा केंद्र: शासकीय विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनेंद्रगढ़, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनेंद्रगढ़ (ई), शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनेंद्रगढ़ (टी), शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालपुर, यूनिवर्सल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मनेंद्रगढ़, सरस्वती शिशु मंदिर झगराखांड

रोड मनेन्द्रगढ़ और सरस्वती विकास विद्यालय मनेन्द्रगढ़ होगा।

परीक्षा व्यवस्था हेतु विशेष निर्देश: परीक्षा प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:15 बजे तक आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ के आधा घंटा पूर्व मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी की हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर व मैनुअल तलाशी की जाएगी।

सीमेंट के पिलर से सिर फोड़कर मर्डर,ताश खेलने के दौरान हुआ था विवाद

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। राजधानी रायपुर में 3 भाइयों ने मिलकर 1 युवक का मर्डर कर दिया। सड़ु के बैरागी बाड़ा में 25 जुलाई की रात ताश खेलने के दौरान विवाद हुआ जिसके बाद तीनों भाइयों ने सीमेंट के पिलर से युवक का सिर कुचलकर उसे मार डाला। मामला विधानसभा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि मृतक देवेंद्र चंदवानी (32 साल) आरोपी अर्जुन बैरागी के घर के पास पहुंचा था और विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी

ने अपने पास रखे चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान अर्जुन के दो सगे भाई डांडी और शाहिल आ गए। उन्होंने सीमेंट के पिलर उठाकर राजा के सिर पर पटक दिया। सिर पर वार लगने से राजा की मौके पर ही मौत हो गई।

चारों तरफ बिखरा खून: घटनास्थल पर चारों तरफ खून बिखर गया था। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जबकि 2 अन्य फरार हैं। पुलिस के मुताबिक, विवाद के बाद उस समय मामला शांत हो गया था।

ग्राम राँपा में हैंडपंप के जल स्रोत में क्लोरीनेशन से ग्रामीणों को मिला स्वच्छ जल का तोहफ़ा



मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले के भरतपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम राँपा के निवासियों के लिए अब पीने का पानी पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और स्वच्छ हो गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्राम में स्थापित हैंडपंप के जल स्रोत में क्लोरीनेशन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं और कीटाणुओं को प्रभावी ढंग से नष्ट किया गया, जिससे अब ग्रामीणों को संक्रमण मुक्त एवं गुणवत्ता युक्त पेयजल मिल रहा है। क्लोरीनेशन की यह पहल ग्रामवासियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बड़ा और कारगर कदम है, जिससे ग्रामीणों को जलजनित बीमारियों से बचाव में सीधा लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि अब तक कई ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता को लेकर चिंता बनी रहती थी,

विशेषकर गर्मियों और बरसात के मौसम में जब जल स्रोतों में प्रदूषण की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा समय रहते इस पहल को अमल में लाना अत्यंत सराहनीय है। विभाग द्वारा नियमित निगरानी, पानी के सैंपल परीक्षण और आवश्यकतानुसार क्लोरीन का उपयोग कर जल स्रोतों को शुद्ध बनाया गया है, जिससे न केवल पेयजल की गुणवत्ता में सुधार आया है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत करते हुए प्रसन्नता जताई है। उनका कहना है कि पहले हैंडपंप के पानी में हल्की दुर्गंध और अस्वच्छता की शिकायत रहती थी, जिससे उन्हें पीने के लिए पानी उबालना पड़ता था। अब क्लोरीनेशन के बाद पानी की गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार देखने को मिल रहा है और बीमारियों की आशंका भी कम हो गई है।

कोरबा में ठेका कंपनी के खिलाफ मजदूरों का प्रदर्शन



मीडिया ऑडीटर, कोरबा (निप्र)। दीपका में शुक्रवार को हेम्स ठेका कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर रेलवे कोल साइडिंग बंद कर दिया। कर्मचारियों ने का आरोप है कि कंपनी और प्रबंधन ने पहले सहमति से स्वीकार की गई मांगों को लागू नहीं किया है। मजदूरों की प्रमुख मांगों में पुराने मजदूरों को कार्य पर रखना, महीने में 4 छुट्टी और उसका भुगतान, राष्ट्रीय छुट्टी डबल पेमेंट, समान काम पर समान वेतन, मेडिकल सुविधा के लिए श्रृंखल कार्ड, पीएफ खाते में पीएफ जमा करना और हाजरी कार्ड और वेतन पर्ची देना शामिल हैं। 5

मजदूरी ने दी आंदोलन की चेतावनी: कंपनी के कर्मचारी मुकेश कुमार मिरी ने बताया कि इससे पहले भी कंपनी और प्रबंधन को पत्राचार किया जा चुका है। उन्होंने कोयला साइडिंग के साइलो के काम को रोक दिया था। मिरी ने चेतावनी दी कि अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

दुर्ग में पकड़ाया ढाई लाख का गांजा यूपी के युवक यहां गांजा बेचने ग्राहक ढूंढ रहे थे; 4 गिरफ्तार



मीडिया ऑडीटर, दुर्ग (निप्र)। जिले में ढाई लाख का अवैध गांजा पकड़ाया है। 24 जुलाई को भिलाई के सेक्टर 6 आयकर भवन के पास 2 युवक गांजा बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाई में 23 किलो गांजा पकड़ा है। मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी उत्तरप्रदेश से यहां गांजा बेचने आए थे। 2 अलग-अलग प्रकरणों में कार्रवाई की गई है। दूसरे मामले में भी 2 आरोपी भिलाई से पकड़ाए गए। चारों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है।

पहले मामले में यूपी के 2 आरोपी गिरफ्तार: पुलिस प्रवक्ता पद्मश्री तंवर ने बताया कि 24 जुलाई को पुलिस सूचना मिली थी कि दुर्ग रायपुर नेशनल हाईवे के किनारे भिलाई में दो युवक अवैध रूप से गांजा बेच रहे हैं। सूचना पर छापे मार कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से चार पैकेट में 2 लाख 12 हजार कीमत की 21.393 किलो गांजा के साथ एक हजार रुपए नगद बरामद किया गया है।

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले में ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत आयोजित अंतिम जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आदर्श विद्या मंदिर हायर सेकेंड्री स्कूल, खोंगापानी में ‘ऑनलाइन सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता’ विषय पर विशेष सत्र का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को साइबर अपराधों और डिजिटल खतरों से सचेत करते हुए उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाना था। इस कार्यक्रम का संचालन जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी डॉ. राहुल वेंकट के निर्देश तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी आर.के. खाती के मार्गदर्शन में किया गया। पुलिस अधीक्षक चन्द्र मोहन सिंह का आयोजन में सराहनीय सहयोग रहा। कार्यक्रम की रूपरेखा मिशन शक्ति



के अंतर्गत जिला मिशन समन्वयक तारा कुशवाहा के नेतृत्व में तैयार की गई, जिन्होंने बालिकाओं के लिए इस सत्र को संवादात्मक, सरल और ज्ञानवर्धक रूप में प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम के मुख्य सत्र में पुलिस विभाग की उषा राजवाड़े ने बालिकाओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी, बैंकिंग फ्रॉड, रैसमवेयर, सॉफ्टवेयर हैकिंग, डी-डॉस अटैक और साइबर जासूसी जैसे जटिल साइबर खतरों से अवगत कराया। उन्होंने सोशल मीडिया के सुरक्षित

उपयोग, पहचान गोपनीयता, पासवर्ड सुरक्षा जैसे विषयों पर व्यवहारिक उदाहरणों सहित मार्गदर्शन दिया। इसी क्रम में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रतिनिधि अंजनी यादव (पी.एल.वी.) ने बालिकाओं को कानूनी अधिकारों, आत्मरक्षा तकनीकों और साइबर शोषण से बचाव के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की महत्ता समझाते हुए बालिकाओं को किसी भी आपात स्थिति में नि:संकोच मदद लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम

में वित्तीय साक्षरता समन्वयक अनोता कुमारी साह ने सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला कल्याणकारी योजनाओं जैसे दू नोनी सुरक्षा योजना, सक्षम योजना, सखी निवास, शक्ति सदन, नारी अदालत, महतारी वंदन योजना, मातृ वंदन योजना और नवा बिहान योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने योजनाओं के लाभों को बालिकाओं की भाषा में सरल रूप से समझाकर उनके आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा स्पष्ट की। वहीं आर.के. खाती ने बालिकाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों, डिजिटल साक्षरता, आत्मरक्षा कौशल और शिक्षा के महत्व पर विस्तार से संवोधित किया। उन्होंने कहा आज की बेटियाँ तकनीकी जागरूकता, आत्मबल और शिक्षा के माध्यम से समाज की संरचना को बदलने की शक्ति रखती हैं। यह जिम्मेदारी हम सबकी है कि उन्हें सुरक्षित, सशक्त और जागरूक बनाया जाए।

इस आयोजन में विद्यालय के

समस्त शिक्षक टीवीवीरेंद्र बहादुर कुमारी साह ने सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला कल्याणकारी योजनाओं जैसे दू नोनी सुरक्षा योजना, सक्षम योजना, सखी निवास, शक्ति सदन, नारी अदालत, महतारी वंदन योजना, मातृ वंदन योजना और नवा बिहान योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने योजनाओं के लाभों को बालिकाओं की भाषा में सरल रूप से समझाकर उनके आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा स्पष्ट की। वहीं आर.के. खाती ने बालिकाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों, डिजिटल साक्षरता, आत्मरक्षा कौशल और शिक्षा के महत्व पर विस्तार से संवोधित किया। उन्होंने कहा आज की बेटियाँ तकनीकी जागरूकता, आत्मबल और शिक्षा के माध्यम से समाज की संरचना को बदलने की शक्ति रखती हैं। यह जिम्मेदारी हम सबकी है कि उन्हें सुरक्षित, सशक्त और जागरूक बनाया जाए।

इस आयोजन में विद्यालय के

इंदौर जिले में मिशन एक्सपोर्ट फॉम एमपी के अंतर्गत कॉफी विद एक्सपोर्टर्स कार्यक्रम का हुआ सफल आयोजन

इन्दौर ,एजेंसी। एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर द्वारा इन्दौर जिले में नए निर्यातकों को प्रशिक्षित करने हेतु %कॉफी विद एक्सपोर्टर्स विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 100 से अधिक निर्यातक, स्टार्टअप एवं ऐसे उद्यमी जो एक्सपोर्ट प्रारंभ करना चाह रहे हैं, उपस्थित हुए। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निर्यातकों एवं नवाचारकों को निर्यात प्रक्रिया, शासकीय सहायता, शासन की योजनाओं, ब्रांडिंग, गुणवत्ता मानकों, वित्तीय प्रबंधन तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अवगत कराना था, ताकि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन एक्सपोर्ट फॉम एमपी का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में निर्यात



क्षमताओं से युक्त उत्पादों की पहचान कर उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, उनके सतत विकास को सुनिश्चित करना तथा निर्यात को बढ़ावा देना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न गतिविधियाँ जैसे कार्यशालाएं, प्रशिक्षण

द्वारा अपने विचार साझा करते हुए बताया गया कि मध्यप्रदेश से 66000 करोड़ से अधिक का निर्यात किया जा रहा है, जिसमें इन्दौर संभाग का योगदान 40 प्रतिशत से अधिक का है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि देश के कई बड़े शहरों का निर्यात हमारे राज्य से तुलनात्मक है, इसलिए हमें इस क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार प्रत्येक उत्पाद जिसमें निर्यात की क्षमता है, को वैश्विक बाजार तक पहुंचाना चाहती है। एमपीआईडीसी के अंदर गठित एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल नए निर्यातकों को मदद के लिए निरन्तर उपलब्ध है। साथ ही इस तरीके की कार्यशालाएं हम क्षेत्र के अन्य जिलों में भी निरन्तर आयोजित करते रहेंगे।

जिला पंचायत की सामान्य बैठक सम्पन्न महाविद्यालय में पौधा रोपण कर किया गया श्रमदान

विदिशा ,एजेंसी। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी की अध्यक्षता में जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई थी। जिला पंचायत के सभागार में सम्पन्न हुई इस बैठक में सभी सम्माननीय सदस्यगणों के अलावा विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत में विगत बैठक के पालन प्रतिवेदन से शुरू हुई उक्त बैठक में सदस्यों द्वारा अनेक सुझावों से अवगत कराया गया जिन पर अमल करने हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों को जिला पंचायत सीईओ द्वारा निर्देशित किया गया है। बैठक में बतलाया गया कि सड़कों पर विचरण करने वाले गौवंश खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें



व एनएच से गौवंशों को सुरक्षित स्थलों पर पहुंचाने के लिए विशेष पहल जिले में की जा रही है इसके लिए चिन्हित छह स्थलों पर अस्थायी गौशाला के स्वरूप को उन्नत किया जा रहा है। वर्षाकाल के दौरान जिले के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो इसके लिए प्रशासन द्वारा पूर्व में

विभाग के मैदानी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए जियो लोकेशन प्रणाली का अनिवार्य क्रियान्वयन प्रस्ताव पर चर्चा कर निर्णय लिए गए हैं। बैठक में खुली नहरी को प्रेशराइज्ड प्रणाली में रूपांतरित कर सिंचाई रकवा बढ़ाने के प्रस्ताव पर बल दिया गया है ताकि सिंचित रकवा में वृद्धि हो सकें। इसके लिए सिंचाई विभाग द्वारा प्राकलन तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। शासकीय भूमि पर गौशाला निर्माण के प्रस्ताव हेतु नेशनल हाईवे के दोनों ओर स्थित शासकीय भूमि पर टीनशेड युक्त बाउण्ड्रीवाल से सुरक्षित गौशालाओं का निर्माण कराए जाने पर बल दिया गया है

विदिशा ,एजेंसी। राजमाता विजया राजे सिंधिया शासकीय कन्या (अग्रणी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय विदिशा में शासन के निर्देशानुसार एनसीसी कैडेट्स एवं वनस्पति शास्त्र विभाग द्वारा एक पेड़ मां के नाम योजना के अंतर्गत पौधा रोपण किया गया। गुलमोहर, अशोक नेम, कर्दंब, बेल, सागौन जैसे महत्वपूर्ण पौधे महाविद्यालय प्रांगण में रोपे गए। प्राचार्य डॉक्टर बीडी अहिरवार ने अशोक का पौधा लगाकर छात्राओं को पर्यावरण का महत्व एवं पौधों की सुरक्षा करने की नसीहत दी। एनसीसी कैडेट्स ने न केवल पौधारोपण किया, बल्कि श्रमदान कर महाविद्यालय कैम्पस को साफ सफाई की, खरपतवार निकाले। प्राचार्य द्वारा स्वयं भी श्रमदान कर छात्रां डॉ. विनीता प्रजापति एवं श्रीमति नीतू दांगी



वरिष्ठ प्राध्यापकों द्वारा भी पौधे लगाए गए। द्वारा किया गया। महाविद्यालय की सभी कार्यक्रम का आयोजन एनसीसी अधिकारी छात्राओं के द्वारा लगाए गए पौधों की सुरक्षा करने का संकल्प लिया गया।

सामाजिक सुरक्षा में ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी पहल

नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने ऊर्जा क्षेत्र में सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए अब तक 3724 आउटसोर्स कर्मियों के ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) कार्ड बनवाए हैं। इस अभियान का लक्ष्य सभी आउटसोर्स कर्मियों का शत-प्रतिशत ईएसआईसी कार्ड बनवाना है। ट्रांसमिशन लाइन के रखरखाव, एक्स्ट्रा हाई टेंशन (ईएचटी) सब-स्टेशनों पर कार्यरत कर्मियों, कंप्यूटर ऑपरेटरों और वाहन चालकों सहित सभी आउटसोर्स कर्मियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से जोड़ने के लिए एमपी ट्रांसको द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से कर्मियों एवं उनके आश्रितों को स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा सुविधा, नगद लाभ, आश्रित लाभ एवं पेंशन जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि ट्रांसमिशन कंपनी में जोरिमापूर्ण कार्य करने वाले इन कर्मियों के लिए पूर्व में आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच हजार से ज्यादा आयुष्मान कार्ड भी बनवाए जा चुके हैं। साथ ही एमपी ट्रांसको ने अपने बाढ़ा सेवा प्रदाताओं के साथ किए गए अनुबंधों में इस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं को अनिवार्य रूप से शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि ट्रांसमिशन कंपनी समय-समय पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधिकारियों के सहयोग से सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करती है, ताकि आउटसोर्स कर्मियों को ईएसआईसी योजना के विभिन्न लाभों की जानकारी दी जा सके। इस पहल से न केवल कर्मियों को, बल्कि उनके परिवारों को भी सामाजिक सुरक्षा का मजबूत कवच प्राप्त होगा।

समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम 30 जुलाई को होगा

हरदा। समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम 30 जुलाई को आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 30 जुलाई को समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में सी.एम. हेल्थलाइन के लॉन्च प्रकरणों, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दी जा रही सेवाओं एवं समाधान एक दिवस के विषयों तथा 100 दिवस से अधिक लॉन्च शिकायतों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में इस बार गृह विभाग अंतर्गत विवेचना में विलंब व लापरवाही करने, समय से प्रकरण में न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने, किसी पक्ष से मिलकर दबाव में सही कार्यवाही अथवा विवेचना न करने संबंधी प्रकरणों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉ. यादव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत हेण्डपम्प के रखरखाव, मरम्मत एवं विशेष खराबी का निराकरण न होने संबंधी, श्रम विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश असंगठित शहरी व ग्रामीरण कर्मकार कल्याण मण्डल योजना के प्रकरणों, राजस्व विभाग के भूमि के सीमांकन संबंधी, ऊर्जा विभाग अंतर्गत बिल में गड़बड़ी संबंधी शिकायतों, कुटीर एवं ग्रामोद्योग अंतर्गत प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से संबंधित प्रकरणों, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत मेडिकल कॉलेज में प्रसूति सहायता योजनांतगत न्यूनतम राशि न मिलने संबंधी प्रकरणों, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक व अन्य द्वारा योजना का लाभ दिये जाने हेतु अनुचित राशि की मांग संबंधी प्रकरणों तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अंतर्गत शिष्यवृत्ति अथवा छात्रवृत्ति संबंधी प्रकरणों की समीक्षा करेंगे।

खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के आग्रह पर केन्द्र सरकार का बड़ा फैसला

नर्मदापुरम ,एजेंसी। प्रदेश के पात्र हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत अब अधिक मात्रा में गेहूँ मिलेगा। वर्षों से लंबित इस मांग को प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सतत प्रयासों को चलते आखिरकार केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब पात्र परिवारों को मिलने वाले खाद्यान्न में 75 प्रतिशत गेहूँ और 25 प्रतिशत चावल वितरित किया जाएगा। जबकि अभी तक चावल और गेहूँ 60 = 40 के अनुपात में वितरित किया जाता था। खाद्यान्न वितरण के इस अनुपात में बदलाव की मांग लंबे समय से की जा रही थी पर निराकरण नहीं हो पा रहा था। खाद्य मंत्री बनने के बाद प्रदेश में विभिन्न जिलों के दौरे पर श्री राजपूत से कई बार जनता के माध्यम से यह अनुरोध सामने आया कि इस सिस्टम में बदलाव कर गेहूँ की मात्रा ज्यादा करते हुए 75 फीसदी और चावल की 25 फीसदी कर दी जाय। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत केंद्र द्वारा राज्यों को खाद्यान्न का आवंटन एक निर्धारित अनुपात में किया जाता है। मध्यप्रदेश में बहुसंख्यक आबादी चावल की तुलना में गेहूँ का अधिक उपयोग करती है, लेकिन पूर्ववर्ती व्यवस्था इसके



विपरीत थी। इस व्यावहारिक विसंगति को दूर करने के लिए मध्यप्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर इस मुद्दे को प्रभावशाली ढंग से उठाया, और मात्र एक सप्ताह के भीतर श्री राजपूत ने केंद्रीय मंत्री श्री जोशी को यह भी अवगत कराया कि मध्यप्रदेश में चावल की आवश्यकता कम है, जबकि अधिक मात्रा में मिलने वाला चावल अक्सर बाजार में औने-पौने दामों पर बेचा जाता है या दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है। इसके विपरीत, यदि हितग्राहियों को उनकी पसंद और जरूरत के अनुसार गेहूँ मिले, तो यह व्यवस्था अधिक प्रभावी और

पारदर्शी हो सकेगी, क्योंकि मध्यप्रदेश में गेहूँ बहुतायत में होता है। इस समस्या के समाधान के लिये मप्र में पात्र हितग्राहियों को दिये जाने वाले खाद्यान्न में गेहूँ की मात्रा बढ़ाई जाना हितकारी होगा। खाद्य मंत्री श्री राजपूत का यह सुझाव केन्द्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी को समसामयिक और नेतृत्व दृढ़ इच्छाशक्ति से निर्णयों को आगे बढ़ाए, तो नीतिगत बदलाव संभव हैं। यह निर्णय सिर्फ अनुपात बदलने का नहीं, बल्कि जनसरोकारों की नब्ब पहचान कर उसे नीति में बदलने का जीवंत उदाहरण है। राज्य के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की पहल आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए भी दिशा दिखा सकती है। पीडीएस को अधिक पारदर्शी और हितग्राही केंद्रित बनाने के लिए आचार्य प्रमाणिकरण, डिजिटल वितरण ट्रेकिंग, और ई-केवाईसी जैसी आधुनिक तकनीकों को तेजी से

लागू किया जा रहा है। श्री राजपूत ने माना केन्द्रीय मंत्री का आभार, बोले, निर्णय से उपयोगिता और स्वीकार्यता बढ़ेगी खाद्य सुरक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण और सारगर्भित त्वरित निर्णय पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी का सहृदयता से आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि पीडीएस के माध्यम से खाद्यान्न में चावल की जगह गेहूँ की मात्रा बढ़ाने के अनुरोध को महज एक हफ्ते के अंदर ही स्वीकार कर उसमें बदलाव के आदेश जारी करना यह बताता है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार जगह के लिए किसी भी निर्णय पर त्वरित अमल करती है। श्री राजपूत ने कहा कि खाद्यान्न उपार्जन से लेकर पीडीएस के माध्यम से खाद्यान्न वितरण तक व्यवस्था में लगातार बदलाव के प्रयास होते रहेंगे। केंद्र से लेकर राज्य तक सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर के व्यक्ति तक सुविधाओं का विस्तार है ताकि कोई पात्र हितग्राही वंचित न रहे। श्री राजपूत ने कहा कि पीडीएस का मूल उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग को खाद्य सुरक्षा देना है।

भगतसिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिपरिया महाविद्यालय में आयोजित हुआ रोजगार कैप

नर्मदापुरम ,एजेंसी।शुक्रवार को शहीद भगतसिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिपरिया में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, जिला प्रशासन एवं जिला रोजगार कार्यालय नर्मदापुरम के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय रोजगार कैप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला रोजगार अधिकारी एवं प्लेसमेंट अधिकारी श्री धर्मेश तिवारी के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ। रोजगार कैप में ट्राइडेंट एवं वर्धमान (बुधनी), शिव शक्ति एग्ग्रीटेक, जेड प्लस, एम.आई.सी., डीडीयू-जीकेवाई, नवभारत सहित कई प्रतिष्ठित निजी कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रतिनिधियों ने उपस्थित विद्यार्थियों को कंपनियों की कार्यप्रणाली, जॉब प्रोफाइल्स एवं चयन प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की। इस रोजगार मेले में कुल 186 विद्यार्थियों ने सहभागिता कर विभिन्न कंपनियों से संबंधित जानकारी प्राप्त की, जिनमें से 95 विद्यार्थियों का प्राथमिक चयन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. राजीव माहेश्वरी के निर्देशन, मार्गदर्शन और सक्रिय उपस्थिति में कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। आयोजन को सफल बनाने में करियर प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. अनिता सेन, प्रो. किटी मौर्य, डॉ. एस. के. मेहरा, प्रो. एस. के. बघेल, डॉ. ए. के. राकेशिया, डॉ. अरुण मोहता एवं महाविद्यालय स्टाफ का विशेष सहयोग रहा। रोजगार कैप में महाविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ-साथ सी.एम. राजन आर.एन.ए. विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने भी भाग लिया और इस अवसर का लाभ उठाया

खरपतवार, कीट एवं फफूंदनाशक दवाईयों का अनुशसित मात्रा में ही किया जाये उपयोग

हरदा। सोयाबीन व मक्का फसलों में खरपतवार नाशक, कीटनाशक, फफूंदनाशक का उपयोग पूरी जानकारी लेकर ही करें। जो कृषि रसायन शोध द्वारा अनुशसित हैं केवल उनका ही उपयोग करें। वैज्ञानिक श्री ओमप्रकाश भारती ने किसानों को सलाह दी है कि 2 या उससे अधिक कृषि रसायनों को मिलाकर स्प्रे करने से बचें, अन्यथा फसल को नुकसान होने या फसल नष्ट होने की भी स्थिति बन सकती है। कृषि रसायन खरीदते समय उसके साथ कंपनी द्वारा दिये गए पत्रक को जरूर पढ़ें। उसमें दवा के विषय में पूर्ण जानकारी व फसल अनुशंसा दी जाती है।

पोषण संजीवनी अभियान के सकारात्मक परिणाम हो रहे परिलक्षित

विदिशा ,एजेंसी। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता की पहल पर विदिशा जिले में पोषण संजीवनी अभियान अंतर्गत कुपोषित बच्चों को सुपोषण किट प्रदाय की जा रही है जिसके फलस्वरूप जिले में क्रियान्वित इस कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं।

इस कड़ी के तहत आज सुफलाम फाउंडेशन इंदौर के द्वारा विदिशा नगर के 72 सैम बच्चों को पोषण संजीवनी किट प्रदान की गई है जिसकी कीमत 3000 रुपये प्रति किट है। किट में निम्न सामग्री उपलब्ध करवाई गई है जिसमें बासमती चावल, गुड़, पाउडर, मूंगफली, दाल, मुरमुरे, अमूल घी, तेल, सफेद तिल, सतु मक्का, आटा, मूंगदाल, किसमिस, भूना चना, बेसन, लंच बाक्स, कम्पाक्स, रेसिपी बुक इत्यादि शामिल हैं। सुफलाम फाउंडेशन इंदौर के जिला प्रभारी डॉक्टर भी ओसवाल एवं डॉक्टर प्रतिभा ओसवाल द्वारा विदिशा शहर के पाँच



आंगनवाड़ी केन्द्र 36 ध/152 (सरिता शर्मा), 34/147 (शिवाली वर्मा), 1/4 (सुधा सक्सेना), 1/2 (वंदनी श्रीवास्तव), 17/108 (रशीदा बी) पर भ्रमण कर सुपोषण किट वितरण किये गये हैं। इस दौरान 18 बच्चों एवं उनके माता-पिता से बच्चों के पोषण एवं उनकी वजन वृद्धि स्वास्थ्य के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें पाया गया कि बच्चों के स्वास्थ्य में एवं वजन में सकारात्मक वृद्धि हुई है। रोजिना की माता श्रीमति नेहा शर्मा ने बताया कि किट वितरण के समय बच्चे का वजन 8.5 किलोग्राम था। किट प्राप्त होने के पश्चात किट में प्रदाय सामग्री का सेवन करने से आज बच्चे का वजन 500 ग्राम तक बढ़ गया है। अक्रमन अंसारी की माता श्रीमति मुस्कान अंसारी ने बताया कि किट वितरण के समय अक्रमन (9 माह) का वजन 4 किग्रा था। अब किट में प्रदाय सामग्री का सेवन करने से बच्चे का वजन 4.700 ग्राम हो गया है।

चार मैचों की सीरीज के लिए भारतीय हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी

नई दिल्ली। भारतीय पुरुष हॉकी टीम आगामी एशिया कप की तैयारियों के तहत 15 से 21 अगस्त तक पर्थ में होने वाली चार मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। विश्व रैंकिंग में आठवें स्थान पर काबिज भारतीय टीम 15, 16, 19 और 21 अगस्त को छठे स्थान पर काबिज ऑस्ट्रेलिया की टीम का सामना करेगी। सभी मैच पर्थ में खेले जाएंगे। वहीं, एशिया कप का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितम्बर तक बिहार के राजगीर में होना है। इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता का विजेता अगले वर्ष के एफआईएच विश्व कप के लिए सीधे क्वालीफाई करेगा। हॉकी इंडिया द्वारा जारी एक बयान में भारत के मुख्य कोच क्रैग फुल्टन ने कहा, “यह दौरा बिहार में होने वाले हीरो एशिया कप से ठीक पहले महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है। भले ही यह मैत्रीपूर्ण सीरीज है लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेलने से हमें खुद को परखने का अच्छा मौका मिलेगा।”

शुभमन गिल ने विराट-रोहित के रिकॉर्ड की उड़ाई धज्जियां

नई दिल्ली। मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। जहां इंग्लैंड की पारी में बैजबॉल देखने को मिला। इंग्लैंड के ओपनर्स ने अपनी पहली पारी में खूब तेजी से रन बनाए। भारतीय गेंदबाज इस दौरान बुरी तरह से फेल नजर आए। जसप्रीत बुमराह, अंशुल कंबोज, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर सभी ने निराश किया। बेन डकेट के साथ मिलकर जैक क्रॉली ने भी भारतीय गेंदबाजों की खूब कुटाई की। इन दोनों ने लगभग पूरी पारी के दौरान हर ओवर में पांच से ज्यादा के रन रेट से बैटिंग की। इसी बल्लेबाजी के दम पर इन दोनों ने भारत के खिलाफ ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो बीते कई सालों से नहीं बन पाया था। मैनचेस्टर में डकेट और क्रॉली ने पहले

विकेट के लिए 166 रन जोड़े। ये इस सीरीज में दूसरी बार हुआ है जब इंग्लिश ओपनर्स ने 150+ रन की साझेदारी की हो। इससे पहले लीड्स टेस्ट में चौथी पारी में भारत के टारगेट का पीछा करते हुए इन दोनों ने 188 रन जोड़े थे। इससे पहले साल 2016-2024 तक भारत के खिलाफ कोई भी टीम 150+ की ओपनिंग साझेदारी नहीं कर पाई थी। यानी इन आठ सालों में भारत ने एक बार भी 150+ की ओपनिंग साझेदारी नहीं होने दी थी लेकिन अब इंग्लैंड ने सिर्फ चार मैचों के अंदर ही दो बार ऐसा ही कर दिया। ऐसे में शुभमन गिल की कसानी में वो काम हुआ है जो विराट कोहली और रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में पिछले आठ साल में एक बार भी नहीं हुआ था।

इस दिग्गज ने कप्तान शुभम गिल को दी सलाह

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। जहां इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने सीरीज में अपनी उम्मीदें बनाए रखने के लिए शुभमन गिल और टीम से आक्रामक मानसिकता अपनाने की गुजारिश की। बता दें कि, मैनचेस्टर में भारतीय टीम की पहली पारी के स्कोर 358 रन के जवाब में इंग्लैंड ने दूसरे दिन स्टंप्स तक 46 ओवर में दो विकेट खोकर 225 रन बनाए। माइकल वॉन ने सीरीज में अपनी उम्मीदें बनाए रखने के लिए शुभमन गिल और टीम से आक्रामक मानसिकता अपनाने की गुजारिश की।

बता दें कि, भारतीय टीम की पहली पारी के स्कोर 358 रन के जवाब में इंग्लैंड ने दूसरे दिन स्टंप्स तक 46 ओवर में दो विकेट खोकर 225 रन बनाए। माइकल वॉन ने सीरीज में अपनी उम्मीदें बनाए रखने के लिए शुभमन गिल और टीम से आक्रामक मानसिकता अपनाने की गुजारिश की।

जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में अपने नाम किया बड़ा कीर्तिमान, इस मामले में द्रविड़-कैलिस को पछाड़ा

नई दिल्ली ,एजेंसी। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। रूट ने भारत के खिलाफ जैसे ही 31 रन बनाए वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गए।

भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच की पहली पारी में खेल के तीसरे दिन इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। रूट ने भारत के खिलाफ जैसे ही 31 रन बनाए वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गए। जो रूट ने राहुल द्रविड़ और जैक कैलिस को एक साथ पीछे छोड़ा और कमाल की उपलब्धि अपने नाम कर ली। जो रूट ने ये उपलब्धि अपने टेस्ट करियर के 157वें मैच में हासिल किया। जो रूट मैनचेस्टर टेस्ट मैच की पहली पारी में भारत के खिलाफ शानदार बैटिंग करते हुए नजर रहे थे और खबर लिखे जाने तक वो 31 रन बनाकर ब्रीज पर मौजूद थे। जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में अब



तक यानी खबर लिखे जाने तक 13,290 रन बना लिए और वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर की लिस्ट में तीसे नंब पर आ गए। तीसरे नंबर पर इससे पहले साउथ अफ्रीका के दिग्ग बल्लेबाज जैक कैलिस था जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 13,289 रन बनाए थे। अब कैलिस चौथे नंबर पर आ गए हैं जबकि द्रविड़ पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं। रूट ने टेस्ट क्रिकेट में अब तक खेले 157वें मैचों की

अब आरसीबी के घरेलू मैदान चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं खेलें जाएंगे आईपीएल मैच?

नई दिल्ली ,एजेंसी। आईपीएल 2026 सीजन के दौरान अब बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोई मैच नहीं खेले जाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार, बेंगलुरु भगदड़ मामले में जांच आयोग ने इस स्टेडियम में बड़े आयोजनों पर रोक लगा दी है। जिससे आरसीबी को बड़ा झटका लगा है। हालांकि, इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं, बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार ने अब आरसीबी के खिलाफ मुकदमा चलाने की भी इजाजत दे दी है।

सरकार का ये फैसला जांच आयोग की रिपोर्ट में आया है, जिसमें आरसीबी और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ को घटना के लिए दोषी बताया गया था। आरसीबी के साथ ही केएससीए पर भी केस चलाने को मंजूरी मिल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम बड़े आयोजनों के लिए असुरक्षित है। इसलिए वहां पर किसी भी बड़े आयोजन पर रोक लगा दी है। ऐसे में अगले साल होने वाले आईपीएल मैचों के यहां होने की संभावना कम ही लग रही है। इस खबर से कहीं न कहीं आरसीबी को बड़ा झटका लगा है



क्योंकि वह अब अपने घर में एक भी मैच नहीं खेल पाएगा। वहीं, जस्टिस डीकुन्हा की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले हफ्ते ही कर्नाटक कैबिनेट

के सामने पेश की गई थी। जिसे गुरुवार 24 जुलाई को मंजूर कर लिया गया। इस रिपोर्ट में ही आरसीबी और चप्पू के अलावा इवेंट

मैनेजमेंट कंपनी केएससीए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट-लिमिटेड को भी दोषी बताया गया था।

भारतीय महिला क्रिकेटर वेदा कृष्णमूर्ति ने लिया संन्यास

नई दिल्ली ,एजेंसी। भारतीय बल्लेबाज वेदा कृष्णमूर्ति ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वेदा ने अपने करियर में 48 वनडे और 76 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। जिनमें उन्होंने क्रमशः 829 और 875 रन बनाए हैं। लेकिन संकेत दिया कि वह किसी अन्य भूमिका में खेल से जुड़ी रहेंगी। वेदा कृष्णमूर्ति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि, एक छोटे शहर की बड़े सपने रखने वाली लड़की से लेकर गर्व से भारतीय टीम की जर्सी पहनने



तक। क्रिकेट ने मुझे जो भी सबक, लोग और यादें दी हैं, उनके लिए आभारी हूँ। अब खेल को अलविदा कहने का समय आ गया है, लेकिन खेल को नहीं। हमेशा भारत के लिए। हमेशा टीम के लिए उपलब्ध रहूंगी। कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर अर्जुन होयसला से विवाह करने वाली 32 वर्षीय वेदा आखिरी बार 2020 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान देश के लिए खेली थीं। उनका आखिरी वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच 2018 में था।

दिल्ली कैपिटल्स के कोच ने ऋषभ पंत को लेकर दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली ,एजेंसी। इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के बल्ले से खूब रन निकल रहे हैं। मैनचेस्टर टेस्ट मैच के दूसरे दिन पैर के अंगुठे में फ्रैक्चर होने के बाद भी उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली। इस सीरीज में पंत अब तक दो शतक और तीन अर्धशतक लगा चुके हैं। हालांकि, अब उनका इस सीरीज में खेल पाना मुश्किल है। वहीं इस दौरान दिल्ली कैपिटल्स के कोच हेमांग बदान ने पंत को भविष्य का टेस्ट कप्तान बता दिया है। साथ ही उन्होंने शुभमन गिल की कसानी की काफी आलोचना भी की। इंडियन प्रीमियर लीग की टीम दिल्ली

कैपिटल्स के हेड कोच हेमांग बदानी ने ऋषभ पंत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि, पंत टीम इंडिया के अगले कप्तान हो सकते हैं। सोनी स्पोर्ट्स पर बात करते हुए हेमांग बदानी ने कहा कि पंत ने खुद को साबित किया है। इस समय वो बल्ले से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बदानी ने कहा कि, आपको उसी पैर के सहारे बल्लेबाजी और दौड़ना होता है। ये साहस का पल था। पंत टीम को बता रहे हैं कि वो इस टीम का लीडर हैं, वो कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है, बल्कि भविष्य का लीडर बनने वाला है। वो फिलहाल टीम का उपकप्तान है, लेकिन पंत एक ऐसा खिलाड़ी बनना चाहता है जिस पर भरोसा

किया जा सके। उसने इस सीरीज में इस बात को साबित भी कर दिया है।



फिलहाल, पंत इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं।

बीसीसीआई से हुए बाहर तो इस टीम ने अभिषेक नायर को बनाया कोच

नई दिल्ली ,एजेंसी। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर अभिषेक नायर को महिला प्रीमियर लीग की टीम यूपी वॉरियर्स का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है। उन्होंने जॉन लुईस की जगह ली है, जो पिछले तीन सीजन से इस भूमिका में थे। टीम ने लगातार दो सीजन में खराब प्रदर्शन के बाद बदलाव की राह चुनी है। नायर के कोचिंग अनुभव और खिलाड़ियों को संवारने की उनकी खासियत ने टीम मैनेजमेंट को प्रभावित किया। अभिषेक नायर का कोचिंग करियर बेहद प्रभावशाली रहा है। 2018 में केकेआर के साथ कोचिंग की शुरुआत करने वाले नायर ने बाद में सीपीएल में त्रिनबागो नाइट्स के कोच की भूमिका भी निभाई। आईपीएल 2024 में उन्होंने केकेआर को तीसरी बार खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद वह भारतीय टीम के सहायक



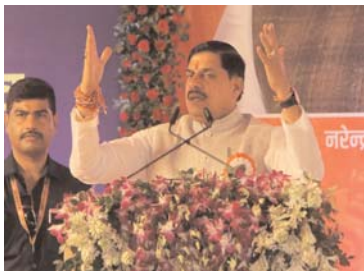
कोच बने, हालांकि, उनका कार्यकाल लंबा नहीं रहा और वो फिर से केकेआर के कोचिंग स्टाफ में लौट गए। वहीं यूपी वॉरियर्स के सीओओ क्षेमल वाईंगनकर ने कहा कि, अभिषेक जैसा अनुभव और विजयी सोच वाला कोच मिलना हमारे

लिए सौभाग्य की बात है। पिछले 18 महीनों में वे तीन अलग-अलग टीमों को चैंपियन बना चुके हैं। हमें विश्वास है कि वह यूपी वॉरियर्स को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। हालांकि, ये पहली बार होगा जब नायर किसी महिला टीम के कोच बने

हैं। लेकिन 2023 में उन्होंने बेंगलुरु में यूपी वॉरियर्स के लिए एक हफ्ते का कैप भी आयोजित किया था। वे पहले भी रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों के करियर में नई जान फूंक चुके हैं।

बहन-बेटियों के लिए सम्मान का प्रतीक है लाइली बहना योजना: मुख्यमंत्री

डॉ. मोहन यादव ने सतना को प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ जिला बनाने का दिलाया संकल्प



महिलाओं की आर्थिक प्रगति के साथ-साथ सामाजिक समरसता और अधिकार सम्पन्नता के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार महिलाओं की आर्थिक प्रगति के साथ-साथ सामाजिक समरसता और सभी की अधिकार सम्पन्नता के लिए सामाजिक रचना के ताने-बाने में प्रत्येक स्तर पर आवश्यक योगदान दे रही है। इसी का परिणाम



है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप किसान, युवा, गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम संचालित हैं। हमारी संस्कृति में देश के लिए मातृत्व भाव विद्यमान है, हम सब भारत माता पर सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर हैं। आज का मातृशक्ति सम्मेलन- माताओं-बहनों के प्रति सनातन संस्कृति के अनुरूप अनन्य श्रद्धा-स्नेह-प्रेम और सम्मान का प्रकटीकरण है। भारत की कुटुम्ब या परिवार परम्परा हमारी संस्कृति को समृद्ध और सशक्त बनाती है। परिवार परम्परा का आधार मातृशक्ति ही है। बेटियाँ एक ही नहीं दो परिवारों का उद्धार करती हैं। बहन-बेटियों के प्रति इस सम्मान के परिणामस्वरूप ही प्रदेश में लाइली बहना योजना आरंभ की गई। सावन के महीने में लाइली बहनों के खाते में 1250 रूपए के साथ-साथ 250 रूपए अतिरिक्त रूप से आने वाले हैं। यह बहन-बेटियों प्रति हमारी सरकार का आदर और स्नेह है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज सतना जिले के सिंहपुर में आयोजित मातृशक्ति



मुख्यमंत्री ने किया 93 करोड़ रूपए से अधिक लागत के 232 कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन

मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने सिंहपुर में मातृ शक्ति उत्सव के कार्यक्रम में 93 करोड़ 19 लाख रूपए लागत के 232 कार्यों का लोकार्पण भूमिपूजन किया। इन कार्यों में 44 करोड़ 7 लाख 28 हजार रूपए लागत के 135 कार्यों का लोकार्पण किया गया। इसी प्रकार 49 करोड़ 11 लाख 80 हजार रूपए लागत के विभिन्न 97 कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर सतना जिले के प्रभारी मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री क्रप्रतिमा बागरी, सांसद गणेश सिंह, विधायक नागोद नागेंद्र सिंह, रामपुर बघेलान विक्रम सिंह, चित्रकूट सुरेंद्र सिंह गहरवार, जिला पंचायत अध्यक्ष रामखेलान कोल, उपाध्यक्ष सुष्मिता सिंह, महापौर योगेश ताम्रकार, स्पीकर नगर निगम राजेश चतुर्वेदी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने दी स्व. जीवनदास बागरी को श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को सतना जिले के ग्राम हरदुआ पहुंचकर नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के पितामह स्व. जीवनदास बागरी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने दिवांगत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना की और शोक संतुष्ट परिजनों से मिलकर ढाढस बंधाया। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री श्री कैलाश विजय वर्गीय ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी, उनके पिता श्री जयप्रताप बागरी एवं परिवार जन तथा सांसद श्री गणेश सिंह भी उपस्थित थे।



उत्सव के अंतर्गत आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लाइली

बहना योजना के अंतर्गत बहनों को जारी की जाने वाली राशि में चरणबद्ध रूप से वृद्धि होगी

और वर्ष 2028 तक बहनों को तीन हजार रूपए

प्रतिमाह उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण और उनके

कल्याण के लिए 1500 करोड़ रूपए से अधिक

प्रतिमाह अंतरित किए जा रहे हैं। प्रदेश की सभी बहनें हमारा मान हैं, अभिमान हैं। इनके मान-सम्मान और कल्याण के लिए हम कोई कसर नहीं रखेंगे। दीपावली के बाद आने वाली भाईदूज तक राज्य सरकार सभी लाइली बहनों को 1250 रूपए से बढ़ाकर हर माह 1500 रूपए सहायता राशि देगी। बहन-बेटियों के सशक्तिकरण के लिए स्व-सहायता समूहों का संचालन, नौकरियों और स्थानीय व नगरीय निकायों और पंचायतों में आरक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी लोकसभा और विधानसभा में बहनों का 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। माताओं-बहनों के कल्याण के लिए ही सभी परिवारों को पक्के मकान, घर-घर गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीदीयां लखपति बनकर प्रगति कर रही हैं, बेटियों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था है, उन्हें साइकिलें उपलब्ध कराने के साथ-साथ परीक्षा में अच्छा परिणाम लाने पर प्रोत्साहन स्वरूप लेपटॉप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। डॉक्टर-इंजीनियर बनने के लिए भी आवश्यक हरसंभव सहायता बेटियों को उपलब्ध है। उद्योगों में काम करने वाली बहनों के लिए भी राज्य सरकार विशेष सहायता प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों की जिन्दगी बदलने के लिए उन्हें बिजली में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सोलर पम्प पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। अगले डेढ़ माह में बरगी नहर का कार्य पूर्ण हो रहा है, इससे रीवा-सतना क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। हमारी सरकार ने हर खेत तक पानी पहुंचाने का संकल्प लिया है और हम इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मानसून में शहर से कट जाता है थर पहाड़ क्षेत्र में सड़क-स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, मरीजों को डोली में ले जाते हैं ग्रामीण



मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। सतना जिले के चित्रकूट नगर पंचायत के वार्ड 15 स्थित थर पहाड़ के आदिवासी हर साल मानसून में चार महीने दुनिया से कट जाते हैं। शनिवार को एक और मामला सामने आया जब प्रसव पीड़ा से तड़प रही शोभा मवासी को डोली में लेकर जाना पड़ा।

बुनियादी सुविधाओं का अभाव: जानकारी के अनुसार, करीब 1500 की आबादी वाले इस पहाड़ी क्षेत्र में न सड़क है, न स्वास्थ्य सुविधा और न ही पानी की व्यवस्था। स्थानीय निवासी सुरेंद्र ने बताया कि रास्ता न होने से एंबुलेंस यहां नहीं पहुंच पाती। बीमारों और गर्भवती महिलाओं को चादर में झोली बनाकर नीचे

लाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले साल बरसात में पांच महिलाओं की डिलीवरी रास्ते में हुई और चार लोगों की इलाज न मिलने से मौत हो गई। **छोटी बावड़ी ही एकमात्र जलस्रोत:** लोगों ने बताया कि पांच पीढ़ियों से एक छोटी बावड़ी ही यहां का एकमात्र जलस्रोत है। न सरकारी नल है, न कुआं और न बोरवेल। लोग जंगल से लकड़ी और पत्ते बेचकर गुजारा करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वोट तो मांगने आते हैं, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी उनका हाल जानने नहीं आता। नगर पंचायत सालाना शुल्क वसूलती है, पर कोई सुविधा नहीं देती।

अविश्वास प्रस्ताव में शामिल जनपद सदस्य लापता पत्नी ने कोटर थाने में दर्ज कराई गुमशुदगी; सतना जाने का कहकर निकले थे

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। रामपुर बघेलान जनपद के 35 वर्षीय सदस्य राम नारायण डोहर रहस्यमय तरीके से लापता हो गए हैं। उनकी पत्नी शकुंतला की शिकायत पर कोटर पुलिस ने गुम ईसान का मामला दर्ज किया है।

गुरुवार को सतना जाने का कहकर निकले: कोटर थाना प्रभारी दिलीप मिश्रा ने बताया कि राम नारायण 24 जुलाई को सुबह 10 बजे सतना जाने की बात कहकर चूंद स्थित घर से निकले थे। शाम तक नहीं लौटने पर पत्नी ने फोन किया, लेकिन मोबाइल



स्विच ऑफ मिला। रात करीब 9 बजे राम नारायण का फोन आया और उन्होंने बताया कि वह सतना में हैं। इसके बाद से उनका फोन

बंद है। **जनपद अध्यक्ष के खिलाफ दिया था अविश्वास प्रस्ताव:** जानकारी के अनुसार,

सतना-चित्रकूट मार्ग को चलायमान न बनाने पर 28 तारीख को 10 बजे से नेशनल हाइवे में करूंगा चक्काजाम: आशुतोष

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)।मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष द्विवेदी ने प्रेस में जारी किए गए बयान में कहा कि मिचकुरिन पुलिया व नायरा पेट्रोल पंप के सामने विशालकाय गड्ढा बना है जिसमें कई लोगो के एक्सीडेंट हुए कई लोगो के हाथ पैर टूटे पर हमारे द्वारा प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करवाने के बावजूद भी आजतक सड़क को चलायमान नहीं बनाया गया आगे श्री द्विवेदी ने कहा इसी प्रकार सतना चित्रकूट मार्ग के मझगवा से सड़को पर भारी भरकम गड्ढे होने से लोगो का चलना दुर्गम हो गया है साथ ही गड्ढे नुमा



सड़क की बदहाली को लेकर शासन प्रशासन को पत्र के माध्यम से अवगत भी करवाया गया लेकिन प्रशासन के कानून में जो तक

नहीं रहेगी जबकि उसी रास्ते से आए दिन जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर कमिश्नर एस्डीएम तहसीलदार का आए दिन निकलना होता है इतना ही नहीं सांसद विधायक व कैबिनेट और राज्य के मंत्री भी उसी रास्ते से होकर गुजरते हैं लेकिन सभी के आंख में काली पट्टी बनी हुई प्रतीत होती है उक्त पत्र में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर गड्ढों की मरम्मत नहीं की तो मैं क्षेत्रिय जनता के साथ 28 जुलाई 2025 को सुबह 10 बजे से चक्काजाम कर उग्र प्रदर्शन करूंगा जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी।

परिवार की सालाना आय 3 रूपए, आय प्रमाण पत्र में गड़बड़ी से वायरल हुआ सर्टिफिकेट; तहसीलदार ने बताया लिपिकीय त्रुटि

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। जिले की कोठी तहसील में एक परिवार का आय प्रमाण पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उनकी सालाना कमाई केवल 3 रूपए दर्शाई गई है। यह मामला 22 जुलाई 2025 को जारी किए गए प्रमाण पत्र से जुड़ा है, जिसमें नयागांव निवासी रामस्वरूप पिता श्यामलाल की कुल वार्षिक आय महज तीन रूपए दर्ज की गई थी। औसतन यह 25 पैसे प्रति माह की आय बनती है। प्रमाण पत्र तहसीलदार सौरभ द्विवेदी के हस्ताक्षर सहित विधिवत रूप से जारी किया गया था।



तो लोग हैरान रह गए। कई लोगों ने इसे मजाक बताया तो कड़्यों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। यह

मामला व्यंग्य और चिंता दोनों का विषय बन गया, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई परिवार एक साल में



केवल 3 रूपए कमा सकता है। **नया सर्टिफिकेट हुआ जारी- तहसीलदार:** मामले को लेकर जब

कोठी तहसीलदार सौरभ द्विवेदी से बात की गई, तो उन्होंने माना कि यह एक लिपिकीय गलती थी। उन्होंने बताया कि जैसे ही यह मामला सामने आया, तत्काल प्रभाव से पुराना आय प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया और नया प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसमें परिवार की वार्षिक आय 30 हजार रूपए दर्ज की गई है। सोशल मीडिया पर लोग अब ऐसी लापरवाहियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि यदि यह प्रमाण पत्र किसी योजना या छात्रवृत्ति के लिए उपयोग में लाया जाता, तो इस गलती का असर कितना बड़ा हो सकता था। प्रशासन की ओर से अब तक इस गलती के लिए किसी जिम्मेदार कर्मचारी पर कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है।

डॉक्टर को कैंची से मारने पहुंचा युवक, गार्ड ने नाकाम किया हमला एक्सीडेंट पीड़ित के रेफर करने पर भड़का



मीडिया ऑडीटर, मेहर (निप्र)। शुक्रवार रात 10 बजे सिविल अस्पताल अमरपाटन में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पर एक मरीज के परिजन ने हमला करने का प्रयास किया। डॉक्टर हिमांशु पांडे आकस्मिक चिकित्सकीय ड्यूटी पर थे। इसी दौरान एक्सीडेंट में घायल दो युवक और एक युवती इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने उनका मेडिकल परीक्षण कर उपचार किया और उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

गार्ड की अंगुली में चोट: एंबुलेंस के आने में देरी होने पर पन्ना जिले के गंज सलेहा निवासी 21 वर्षीय विक्रम शर्मा (पिता पंकज शर्मा) गुस्से में आ गया। उसने अस्पताल की एक बड़ी लोहे की कैंची लेकर डॉक्टर पर हमला करने के लिए चैंबर में प्रवेश किया। यहां ड्यूटी पर मौजूद गार्ड अरुण सिंह और ललन सिंह बघेल ने

समय रहते आरोपी को पकड़ लिया। इस दौरान गार्ड अरुण सिंह के बाएं हाथ की अंगुली में चोट भी आई। **गार्ड नहीं पकड़ता तो जान जा सकती थी:** डॉक्टर हिमांशु पांडे ने बताया कि अगर गार्ड ने आरोपी को नहीं पकड़ा होता तो उनकी जान जा सकती थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज अस्पताल में उपलब्ध है। मामले में अमरपाटन थाने पहुंच गया है। डॉक्टर ने आरोपी के खिलाफ मेडिकल प्रोटोकॉल एक्ट और जान से मारने के प्रयास की धाराओं में कार्रवाई की मांग की है। **आरोपी घायल के साथ:** थाना प्रभारी अमरपाटन विजय सिंह परस्ते ने बताया कि आरोपी घायल मरीजों के साथ चला गया था। इसलिए अभी चैंबर में प्रवेश किया। यहां ड्यूटी पर मौजूद गार्ड अरुण सिंह और ललन सिंह बघेल ने मामला दर्ज कर लिया गया है।

भारतीय सिंधू सभा की राष्ट्रीय बैठक मुंबई में आयोजित, गोपी गेलानी हुए रवाना

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। राष्ट्रीय समाजसेवी संस्था भारतीय सिंधू सभा की राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा की बैठक दिनांक 27 28 जुलाई को मुंबई में सख्खर सिन्धी पंचायत भवन,वडाला में आयोजित की गई है।

सतना शाखा के महामंत्री विनोद गेलानी ने जानकारी देते हुए

गेलानी जी महेश ठारवानी बताया बैठक भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश से 24 सदस्यीय प्रतिनिधि दल आज मुंबई रवाना हुआ जिसमें मुख्य रूप से गेलानी जी महेश ठारवानी लालचंद लालवानी सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों से प्रतिनिधि उक्त बैठक में शामिल होंगे।

